असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 फरवरी, 2020

षोडश विधान सभा 28 फरवरी, 2020 ई0

पंचदश सत्र शुक्रवार, तिथि 09 फाल्गुन, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

(व्यवधान)

क्या हुआ ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार में 50 लाख गरीबों को उजाड़ा जा रहा है.....

अध्यक्ष : यह किस चीज पर आप बोल रहे हैं ?

श्री सत्यदेव राम : गरीबों के उजाड़ने पर बोल रहे हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनके सवाल पर बोल रहे हैं और उस पर हमने कार्य-स्थगन दिया है ।

अध्यक्ष : यह समय नहीं है, गरीबों की बात उठाने का ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, जब आदमी नहीं रहेगा तो समय क्या रहेगा, अभी तो उनको बचाने की जरूरत है और इसके लिए समय.....

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0)के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : चलिये, जगह पर जाइये । जगह पर जाइये । महबूब जी, जिस विषय को आप उठा रहे हैं, आप एक मिनट के लिए जगह पर जाइये, सुन तो लीजिए न । जिस विषय को आप आज उठा रहे हैं, कल इसपर विस्तृत चर्चा हुई है, सरकार का भी जवाब आया है और सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि किसी गरीब को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जायेगा । आसन से हमने भी नियमन दिया है कि चूंकि सरकार की यह घोषित नीति है, अगर किसी माननीय सदस्य को यह सूचना मिलती है कि किसी गरीब को किसी इलाके में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा गया है तो उसकी सूचना दीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी । मगर आपको कोई अच्छा से लिखनेवाला उपलब्ध हो जाता है तो कुछ भी लिखवाकर चले आते हैं ।

(व्यवधान)

टर्न-01/28-02-2020/शंभु

अब जगह पर जाइये । आप बिना नियम के गरीब की बात को उठाकर गरीबों की बातों का सम्मान घटा रहे हैं । आप अब जाइये, जगह पर जाकर बोलिये ।

(व्यवधान)

जगह पर जाइये न । आप समय पर उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

सदन में गरीबों की बात उठाने का स्पष्ट नियम है आपको समझना पड़ेगा । चलिये जगह पर जाइये ।

(व्यवधान)

सत्यदेव जी, आप बोल रहे हैं यहां सदन के सदस्यों को सुनाने के लिए कि आप चाहते हैं कि आप यहां बोलिये और सुनाई दरौली में पड़े । अब जगह पर जाइये ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों का हित नहीं चाहते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए उनको नहीं हटाया जायेगा और बार-बार सरकार के आश्वासन के बाद भी इस तरह से रोज तख्ती लेकर आते हैं और कितना महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों को ये बाधित करना चाहते हैं । ये आर0जे0डी0 के नेता को जिस तरह से छपास रोग लगा हुआ है, इसी तरह से इनको भी अब छपास रोग की बीमारी लग गयी है । ये गरीबों को घर दे रहे हैं, गरीबों को कार्ड दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : श्रवण जी, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों काफी समझदार माननीय सदस्य हैं । देखिए, अभी अपनी जगह पर जायेंगे ये, चले जाईये । अब आप जाइये । ठीक है, अब जगह पर जाइये ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण वेल में बैठ गये)

अब अल्पसूचित प्रश्न संख्या-8, श्री सदानन्द सिंह । श्री रामदेव राय जी प्राधिकृत हैं ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-8 (श्री सदानन्द सिंह)</u>

(मा0 सदस्य,श्री रामदेव राय प्राधिकृत)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को राज्य में सूचीबद्ध होने के लिए अब तक 733 निजी अस्पतालों से आवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त आवेदनों में से अब तक 230 निजी अस्पताल नियमानुसार सूचीबद्ध किये गये हैं । कुल 269 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं एवं 207 आवेदन प्रक्रियाधीन है, जिसमें से 190 आवेदन डिस्ट्रीक्ट इम्पेनलमेंट कमिटी के स्तर पर लंबित है । इन आवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित जिलों को निदेश दिये गये हैं । जिला से प्राप्त प्रतिवेदन पर निर्णय लेने हेतु स्टेट इम्पेनलमेंट कमिटी की बैठक प्रत्येक मंगलवार 4 बजे अप0 में निर्धारित है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना, जो गरीबों के हित में था, उसको ये मंगल बाबू अमंगल कर रहे हैं । 23 सितम्बर, 2018 से आयुष्मान भारत योजना मात्र 607 निजी अस्पतालों के निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है । यानी ढाई वर्ष में मात्र 660 और 19 दिसम्बर तक 183 निजी अस्पतालों का निबंधन सरकार द्वारा किया गया है । इसलिए सरकार जो बता रही है कि इतने आवेदन प्राप्त हुए और इतना का निष्पादन हुआ तो ये सरकार सरासर कहीं से गलत रिपोर्ट पर आधारित है, अगर यह बात है तो अभी सरकार बतावे कि किन-किन स्तरों पर इतना विलंब हुआ है और जो विलंब किये हैं, उनको चिन्हित कर ये दंड देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, पढ़कर प्रश्न पूछते, उससे बढ़िया हमारा जवाब सुने होते ठीक से तो जो प्रश्न पूछे, वह प्रश्न नहीं आता। उन्होंने पूछा किस-किस स्तर पर लंबित है । मैंने पूर्व में ही बताया कि कुल 733 आवेदन प्राप्त हुआ है, 230 निजी अस्पताल नियमानुसार सूचीबद्ध किये गये हैं, 269 के आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं, 207 का आवेदन प्रक्रियाधीन है । इसमें से 190 का डिस्ट्रिक्ट इम्पेनलमेंट कमिटी के स्तर पर लंबित है और स्टेट इम्पेनलमेंट कमिटी की मीटिंग प्रति मंगलवार को 4 बजे होती है और संख्या भी मैंने कहा उसको भी माननीय सदस्य सुधार लें 230 निजी अस्पतालों का हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि यह जो इम्पेनलमेंट होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन अप्लीकेशन प्राइवेट हॉस्पीटल को देना होता है । माननीय सदस्य ढाई साल बोल गये, लेकिन इस योजना का ढाई साल नहीं हुआ है, केवल अभी डेढ़ साल हुआ है

और आवेदन प्राइवेट हॉस्पीटल को ऑनलाइन देना पड़ता है, उसके लिए हर स्तर पर जिस अस्पताल को इम्पेनल करना होता है, उस अस्पताल के अंदर कैसी सुविधा है, कैसी सुपर स्पेशलिटी है, किस स्तर के डाक्टर हैं, कैसा उपकरण है, उसके लिए मानक बना हुआ है और उस मानक के अनुसार जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर जॉच होता है उसके उपरान्त मान्यता दी जाती है । ऐसा नहीं है कि कोई भी आवेदन दे देगा और उसको हम मान्यता दे देंगे । कल होकर वहां मरीज जायेगा, कोई दुर्घटना हो जायेगी तो कौन जिम्मेवार होगा ? इसलिए यह पूरी प्रक्रिया बनी हुई है और स्पष्ट तौर पर जवाब मैंने माननीय सदस्य को दिया है ।

श्री रामदेव राय : मैं भी स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बचे आवेदन हैं उनका निष्पादन कब तक आप करा देंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, यह एक सतत् प्रक्रिया है । कोई ऐसा नहीं है कि आज जितना आवेदन आ गया तो हो गया और भी हॉस्पीटल लगातार आवेदन देते रहते हैं और मैंने अभी तक के अद्यतन स्थिति के बारे में बताया है कि 190 आवेदन डिस्ट्रिक्ट इम्पेनलमेंट कमिटी के स्तर पर लंबित है, शेष स्टेट इम्पेनलमेंट कमिटी के पास है । हर मंगलवार को हमारी मीटिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट से जब वह रेफर होकर हमारे स्टेट इम्पेनलमेंट कमिटी को आता है तो फिर यहां से स्वीकृति दी जाती है और अभी तक 230 निजी अस्पतालों को इस इम्पेनलमेंट के अंदर लिया गया है ।

अध्यक्ष : हो गया, अब सब जवाब तो आ ही गया ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-9(श्री ललित कुमार यादव)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-10(श्री शिवचन्द्र राम)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत बल 10609 के विरूद्ध कार्यरत बल 4172 है तथा रिक्त पद की संख्या 6437 है । स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिक्त कुल 6437 चिकित्सकों अर्थात् 2425 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 4012 सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग की कार्रवाई की जा रही है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा

पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी । राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड-ए के कुल स्वीकृत बल 14198 के विरूद्ध कुल कार्यरत बल 5068 है तथा रिक्त पदों की संख्या 9130 है । इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जा रही है ।

टर्न-2/28-02-2020/ज्योति-मुकुल

क्रमशः

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : राज्य में ए.एन.एम. के कुल स्वीकृत बल 27,500 के विरुद्ध कार्यरत बल 17,934 है शेष रिक्त पदों की अधियाचना हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर कोटिवार नियुक्ति की मांग पत्रांक-206, दिनाँक 7-2-2020 एवं पत्रांक-3136, दिनाँक 24-6-2020 द्वारा की गयी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजने के उपरांत उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारी, गेड-ए नर्स एवं ए.एन.एम. की पदस्थापना की जा सकेगी ।

श्री शिवचंद्र राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किया है लेकिन जो हाल बढ़ता बिहार, खिलता बिहार, इस तरीका का आधा-आधा पद जब खाली रहेगा महोदय तो कैसे खिलेगा बिहार, कैसे बढ़ेगा बिहार और लोगों का इलाज कैसे होगा । हम यह जानना चाहत हैं कि डॉक्टर के लिए या उनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और प्रक्रिया के लिए आयोग में कब ये भेजे । फिर ए.एन. एम. या उप चारिका जो ए-ग्रेड का है, उसके लिए इन्होंने कब जो है कि वैकेन्सी निकाली और उसको कब आयोग में भेजने का काम इन्होंने किया । ए.एन.एम. की प्रक्रिया इनकी चल रही है तो यह प्रक्रिया कब से चल रही है यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, बहुत अच्छा विषय माननीय सदस्य ने रखा है । मैं पूरे सदन को दो मिनट समय लगेगा पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है राज्य में चिकित्सकों की कमी है ।

श्री सत्यदेव सिंह : क्यों कमी है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मेरी बात तो सुन लीजिये, सुनियेगा तब न ? अब सुनियेगा नहीं तो कैसे होगा, सत्यदेव बाबू को जवाब से मतलब नहीं होता है । महोदय, जो

चिकित्सकों की कमी है और नर्स की कमी है, माननीय सदस्य को और पूरे सदन को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था, आजादी के बाद पहली बार मैं जो बोल रहा हूँ । पहले पूरी बात तो सुन लीजिये अवधेश बाबू, आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 6,437 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है । यह पहली बार हो रहा है महोदय और एक साथ मैं एक साथ कह रहा हूँ कि एक साथ साढ़े छः हजार डॉक्टरों का। अध्यक्ष महोदय, पहले जो चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती थी, इसमें काफी विलम्ब होता था, हम सब जो माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं सबको ध्यान में होगा कि नियुक्ति में 3,4,5 साल लग जाता था, एक लंबी प्रक्रिया होती थी और उस प्रक्रिया को शॉर्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम सब लोगों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग बनाया और माननीय शिवचंद्र राम जी ने जो जानना चाहा है यह तकनीकी सेवा आयोग लगभग डेढ़ साल पहले कार्य रूप लिया है इस आयोग ने और यह नया आयोग गठित किया गया, जिसमें तकनीकी सेवा के लिए लोगों को चयनित किया जाना है और उसके गठन के बाद आयोग ने अपना पूरा कार्यभार संभाला, उसमें उसको तीन-चार महीना लगा फिर विभाग की तरफ से पिछले साल मार्च-अप्रैल के महीने में यह अधियाचना चिकित्सकों के और ग्रेड-ए नर्स के इसके अलावे पारा मेडिकल स्टाफ की अधियाचना बिहार तकनीकी चयन आयोग को भेजी गयी । फिर यह काम उस आयोग का था, वहां से विज्ञापन निकाला कौन्सिलिंग करना और अप्रैल के बाद से वहाँ यह प्रक्रिया शुरू हो गयी । उसके बाद वहाँ विज्ञापन निकाला गया लोगों ने आवेदन दिया जो आपत्ति निस्तारण करना था वह हुआ और पिछले नवम्बर के महीने से कौन्सलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गयी मेडिकल-ऑफिसर की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कौन्सलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है जो 2,425 डॉक्टर का होना है और जो मेडिकल-ऑफिसर का होना था 4,012 का उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर हो गया । सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौन्सिलिंग को तत्काल रोक दिया अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को तो मानना ही पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में हमलोगों ने अपने पक्ष को रखा और फिर तब वहाँ से क्लियरेंस मिला, उसके बाद अभी फिर 18 फरवरी को उनके निर्णय के आलोक में हमने फिर विज्ञापन प्रकाशित किया और इस 28 तारीख तक उसके आधार पर फिर

से कुछ नये लोग उसमें आवेदन दे सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम जो कौन्सिलिंग की प्रक्रिया है, यदि यह बीच में व्यवधान नहीं आया होता तो आज हम पोस्टिंग करने की स्थिति में पहुंचे होते, लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी वहां पर ग्रेड-ए नर्स की कौन्सिलिंग का काम चल रहा है और 20 मार्च तक जो ग्रेड-ए नर्स का चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद पोस्टिंग के काम में विभाग लग जाएगा और जो चिकित्सकों के कौन्सिलिंग का काम है वह 28 तारीख तक उनको आवेदन देना है और फिर 7 दिन आपत्ति के लिये दिया जाता है । मार्च महीने के अंत तक इसके कौन्सिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से मुझे और सूचना विभाग को सूचना दी गई है । इसलिए माननीय शिवचंद्र राम जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया कि यह सारी प्रक्रिया कब शुरू हुई, कब हमने अधियाचना भेजा, कब कौन्सिलिंग हुई, अभी लेटेस्ट स्थिति क्या है । ये सारा विषय मैंने माननीय सदस्य के ध्यान में डाला है।

श्री शिवचंद्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम जो जानना चाहते थे माननीय मंत्री जी से ये तो विस्तार से किताब पढ़कर के हमको बता दिये ।

अध्यक्ष: आपके ही सवाल का जवाब दिये हैं ।

श्री शिवचंद्र राम : मेरा सवाल यह है, साफ सवाल है ये बोल रहे हैं कि डेढ़ साल पहले तो उस डेढ़ साल की तिथि भी तो होगी, ये सिर्फ गोल-मटोल बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष : वे आयोग की बात कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी तक वह कर लिए होते, 31 मार्च तक सब कर लिया जायेगा अब इससे साफ क्या होगा ?

श्री शिवचंद्र राम : नहीं, नहीं 31 मार्च को कर लिया जायेगा इसमें ये बोले हैं कि हमारे आयोग और आयोग में चिकित्सकों की बात इन्होंने कहा है कि 2,500 चिकित्सक डॉक्टरों की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी, 2,500 डॉक्टरों की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी तो उनकी नियुक्ति कब की जायेगी ? दूसरी बात है कि हमारा साफ कहना है ।..

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि मार्च में हम सब कर लेंगे।

श्री शिवचंद्र राम : नहीं, नहीं जिसका रोक लगा था उसके बारे में बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी थी हमलोग फिर से विज्ञापन दिए हैं बाकी छूटे हुए लोग भी आवेदन दे सकते हैं और 6 हजार वैकेन्सी है सब पर हम मार्च में अभी तक के प्लैनिंग के हिसाब से कर देंगे और क्या जानना चाहते हैं।

श्री शिवचंद्र राम : यह सब तो चिकित्सकों का मामला है लेकिन हम जानना चाहते हैं ए.एन. एम. के बारे में ।

अध्यक्ष : उसका तो कौन्सिलिंग चल रहा है ।

श्री शिवचंद्र राम : ए.एन.एम. के लिए कब से शुरुआत किए हम वह जानना चाहते हैं । ए.एन. एम. पर कोई रोक नहीं था ।

अध्यक्ष : वह तो बतायें । यह प्रक्रिया कबतक हो जायेगी मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम जवाब में बोले थे उसके लिए रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है उसके लिए पत्र निर्गत हुआ यह जानकारी हमने जवाब में ही दी है ।

श्री शिवचंद्र राम : कब से चल रहा है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11 (श्री संजय सरावगी)</u>

श्री संजय सरावगी : मैं पूछता हूँ लेकिन यह प्रश्न जो है मैंने वन एवं पर्यावरण विभाग पर लगया था और यह आपदा में आ गया है यह तो वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रश्न है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपने जगह पर चले जायं ।

अध्यक्ष : श्रवण जी, आप अनुरोध कर रहे हैं तो आप यह समझ लीजिये कि माननीय तीनों सदस्य जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों संवेदनशील भी हैं । आप कह रहे हैं, इधर से सिद्दीकी साहेब कह रहे हैं और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसलिए वे जरूर बात मानेंगे और यह पूरे सदन की उम्मीद है, इसलिए हम आप तीनों माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि आप को कह दिये कि उजाड़ा नहीं जायेगा तो कौन कागज वापस लेना-देना । आप अपना कागज वापस ले ही नहीं रहे हैं । चलिए अपना कागज लेकर जगह पर तो जाईये । चलिए, आप बहुत अच्छे माननीय सदस्य हैं जगह पर जाईये ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : एक दिन हमने अनुरोध किया था कि आप पूरे सदन को बतला दीजिये कि इतना अच्छा लिखने वाला आपको कहाँ धरा जाता है, कहाँ से पकड़ लेते हैं उसको चलिए ।

(व्यवधान)

अब इसपर बहस होगी । अब ये भी संवेदनशील हो जायेंगे ।

(इस अवसर पर वेल में बैठे भाकपा माले के माननीय
सदस्यगण अपने स्थान पर चले गए ।)

(व्यवधान)

टर्न-03/कृष्ण/28.02.2020

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं यह बोल रहा था कि मैंने यह प्रश्न वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से पूछा था । उसी विभाग का यह प्रश्न है । पता नहीं, यह प्रश्न आपदा प्रबंधन विभाग में कैसे चला गया ? मेरे पास उस प्रश्न का फोटो कॉपी भी है, प्रश्न वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से मैंने पूछा है ।

अध्यक्ष : आपका चूंकि अंतिम ऑपरेटीव पार्ट है, जिसमें आप मुआवजा की बात कर रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : सर, यह प्रश्न वन्य प्राणियों द्वारा मानव की मृत्यु होती है, उसके लिये मुआवजा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग ही देता है । इसीलिये मैंने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष : ठीक है । सही जगह चला गया है ।

श्री संजय सरावगी : सर, यह स्थानान्तरण हो गया ?

अध्यक्ष : हो गया ।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 402 (श्रीमती भागीरथी देवी)</u>

अध्यक्ष : श्रीमती भागीरथी देवी । आपके प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है । आप पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं ? माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, आप उत्तर पढ़ दीजिये । माननीय सदस्या उत्तर पढ़ी ही नहीं है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय,खंड-1 आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत एल0टी0के खुले तारों को एरियल बंच केबल किये जाने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत इस तरह के कार्य को अंडरग्राउंड केबल से कार्य करने की स्वीकृति नहीं है । आई0पी0डी0एस0 योजनान्तर्गत रामनगर शहर के सभी जर्जर एल0टी0 तारों को ए0बी0 केबल में बदलकर विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है । इसके अन्तर्गत कुल 9 किलोमीटर जर्जर एल0टी0 तारों को बदला गया है । स्वीकृत योजना के अन्तर्गत शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च,2020 है ।

अध्यक्ष : अगले माह पूरा हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–403 श्री मुजाहिद आलम, माननीय सदस्य श्री नौशाद आलम जी को पूछना है । प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 403 (श्री मुजाहिद आलम)

(माननीय सदस्य श्री नौशाद आलम अधिकृत)

श्री लक्ष्मेश्वर राय,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभिलेख सख्या–37/18–19 लाभुक मो0 शाह आलम, अभिलेख संख्या–402/17–18 लाभुक सलेमा खातून से संबंधित अभिलेख पर मुआवजा के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । भुगतान की कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर कर दी जायेगी ।

श्री नौशाद आलम : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत लेट होता है । सालो–साल लग जाते हैं । माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त वहां पर जो भी घटनायें हुई हैं, उसका जल्द से जल्द करायें ।

अध्यक्ष : आप निर्देश दे दीजिये, सब जगह जल्दी से निष्पादन कर दे ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय,मंत्री : जी अच्छा ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 404 (श्रीमती आशा देवी)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : स्वीकारात्मक है । वस्तु स्थिति यह है कि स्वास्थ्य उप केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जाता है । उप स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा टीकाकरण एवं प्रसवपूर्व जांच की जाती है । इस हेतु स्वास्थ्य उपकेन्दों में ए0एन0एम0 की पदस्थापना की जाती है । हेतनपुर स्वास्थ्य उपकेन्द्र में रश्मि कुमारी एवं श्रीमती किरण कुमारी ए0एन0एम0 कार्यरत हैं । मानस स्वास्थ्य उपकेन्द्र में श्रीमती शोभा कुमारी एवं श्रीमती साधना कुमारी ए0एन0एम0 कार्यरत हैं । पतलापुर में कोई स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है ।

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सर, वहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, डॉक्टर का नाम भी बता रहे हैं लेकिन वहां वे उपस्थित नहीं रहते हैं । प्रभारी को कहा जाय कि वहां कभी–कभी जा कर जांच किया करें । सर, वहां डॉक्टर ही नहीं जाते हैं । सर, इसको दिखवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र में डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होती है । वहां सिर्फ टीकाकरण के लिये ए0एन0एम0 वगैरह रहती हैं । वहां पर डॉक्टर नहीं हैं ।

श्रीमती आशा देवी : सर, वही तो हम बता रहे हैं । कोई कभी नहीं जाते हैं । वहां कभी कोई डॉक्टर टीकाकरण करने नहीं जाते हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि सदन की जो व्यवस्था है, बार-बार मेरी ओर ऊंगली दिखाकर बोलना शायद मुझे लगता है कि यह सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है । माननीय सदस्य बार-बार ऊंगली दिखा रहे हैं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन व्यवहार थोड़ा बेहतर होना चाहिए । यह जरूर मैं अपेक्षा रखता हूं ।

श्री शकील अहमद खान : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : पूछिये ।

श्री शकील अहमद खान : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने इसका तो जवाब दे दिया । सर, जब मेरे इलाके में 30 बेडेड हॉस्पीटल में ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील जी, अभी मामला स्वास्थ्य उपकेन्द्र से है । 30 बेडेड हॉस्पीटल से नहीं है ।

श्री शकील अहमद खान : सर, स्वास्थ्य से रीलेटेड है । जब आप बने हुये 30 बेडेड हॉस्पीटल में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं और मैं पहले ही इन्टरवेन करना चाहता था, कहते हैं कि लास्ट 15 ईयर्स में ऐतिहासिक रचना हो गया, एक साल छोड़कर 14 ईयर्स में हो गया । यह है सिचुएशन ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या - 405 (श्री राम विलास पासवान)</u>

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है । माननीय सदस्य, आप उत्तर पढ़े हैं ?

श्री राम विलास पासवान : नहीं पढ़े हैं सर ।

अध्यक्ष: नहीं पढ़े हैं । माननीय मंत्री, उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कुरमा पंचायत के कुरमा गांव में ही स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, जो चन्नो गांव से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । चन्नो गांव की आबादी ढाई हजार के लगभग है जबकि मानक के अनुरूप प्रत्येक 5 हजार की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र

प्रावधानित है । अतएव यहां कोई भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की कोई भी योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूरे पंचायत की आबादी लगभग 10 से 11 हजार है और वह झारखंड की सीमा पर अवस्थित है और वहां से अनुमंडल अस्पताल 10 से 11 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो वी0आई0पी0 क्षेत्र में है और वहां की सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, वहां तक ले जाते-जाते रोगी की मृत्यु हो जाती है । मैं इसके पूर्व भी आग्रह किया था, प्रश्न भी किया था, आज तक कुछ हुआ नहीं और अध्यक्ष जी, एक बात हम कहना चाहते हैं कि सारे मंत्री फोन उठाते हैं, उनसे मुलाकात भी हो जाती है लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, न तो इनका फोन लगता है और न फोन उठाते हैं ।

अध्यक्ष : यह आप कहां से उठा रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : सर, यह भी इसी में है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री, महोदय, महोदय, ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, हम पांच दिन माननीय मंत्री जी के ऑफिस में गये, इनसे भेंट नहीं होती है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, इस विषय पर विपक्ष के माननीय सदस्यों से वोट करा लीजिये।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, न इनसे फोन पर बात होती है और न ऑफिस में भेंट होती है ।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वहां की 11 हजार की आबादी है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बहुत बड़ी वहां आबादी है और वह झारखंड सीमा पर है ।

अध्यक्ष : ठीक है । उसको माननीय मंत्री जी देखेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू राम, प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 406 (श्री लाल बाबू राम)</u>

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल सकरा में चिकित्सकों के 4 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध संप्रति

2 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं । राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों की भारी कमी है । इस कमी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2425 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 4012 सामान्य चिकित्सकों अर्थात् 6,437 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग भेजी जा चुकी है, जिसके आलोक में नियुक्ति हेतु कॉउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह स्पष्ट नहीं है । मेरा स्पष्ट कहना है कि रेफरल अस्पताल सकरा में 14 पद पहले से सृजित है। सर, सुना जाय ।

क्रमशः

टर्न-4/राजेश-राहुल/28.2.20

श्री लाल बाबू राम, क्रमशः महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है कि वहॉ पर रेफरल अस्पताल सकरा में 14 पद पहले से सृजित है.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी तो सही कह रहे हैं ।

श्री लाल बाबू रामः सर, सुना जाय । वहॉ पर 14 पद सृजित है, पहले से भी 10-12 डाक्टर रहा करते थे लेकिन तीन साल से वहॉ पर मात्र एक डाक्टर है, एक भी स्त्री विशेषज्ञ नहीं है, न तो ऑर्थोपेडिक सर्जन वहॉ पर है और रेफरल हॉस्पिटल होने के नाते वहॉ 37 पंचायत का विधान सभा है प्लस वहॉ पर रेलवे लाईन है, एन0एच0 है, वहॉ पर बराबर घटना दुर्घटना होती रहती है, तो ऐसे पोजिशन पर वहॉ तत्काल प्रभाव से माननीय मंत्री जी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक डाक्टर और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को तत्काल प्रभाव से वहॉ पर प्रतिनियुक्त करने की कृपा करें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय मैंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया मॉर्च के अंतिम तक पूरी हो जायगी, चिकित्सक उपलब्ध होने के बाद मैं प्रतिनियुक्त कर दूंगा ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, हमने नहीं सुना ।

अध्यक्षः उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है जिसके बारे में उन्होंने अभी पिछले प्रश्न के जवाब में कहा है कि मार्च में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जायगी और

आपको कह रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, तो आपके अस्पताल में हम पोस्टिंग कर देंगे । माननीय ललित बाबू पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने कहा कि 14 पद सृजित है और एक डाक्टर है, हम माननीय मंत्री जी के जानकारी में देते हैं कि रेफरल अस्पताल हम लोगों के यहॉ मनीगाछी में भी है, एक दिन भी अस्पताल नहीं खुलता है, कुत्ता बिल्ली, चूहा, बेड पर है, माननीय मंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वे आज ही जांच इसकी करावें ।

अध्यक्षः क्यों चुनौती दे रहे हैं, आप अपने यहॉ की बात कह रहे हैं तो चुनौती क्या, सूचना न दीजियेगा ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, हम इनको चुनौती दे रहे हैं ये जांच तो करा लें ।

अध्यक्षः आप चुनौती क्यों दे रहे हैं, आप सूचना दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादवः दूसरी बात .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः चलिये । अब तारांकित प्रश्न संख्याः 407, मा0सदस्य मो0 नेमतुल्लाह ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मेरी बात को सुन तो लिया जाय.....

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः 407 (श्री मो0 नेमतुल्लाह)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1:- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

खण्ड 3: वस्तुस्थिति यह है कि यहॉ अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किये जाने का निर्णय लिया गया है । समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा भूमि भी उपलब्ध करायी गयी थी, परन्तु भूमि विवादित होने के कारण मामला न्यायालय में लंबित है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करा दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य नेमतुल्लाह जी, अभी आप बैठ जाइये । ललित यादव जी, आप पुराने सदस्य हैं, खुद इस बात को आप 10 बार बोलते हैं कि हम पुराने सदस्य हैं और प्रश्न लाल बाबू राम जी का .....

(व्यवधान)

फिर आप बीच में बोलने लगे, क्या पुराने सदस्य का यही लक्षण होता है और अगर आपकी इच्छा है, बार–बार बोलते हैं कि सदन नहीं चलेगा, तो आप अकेले सदन को रोक देना चाहते हैं तो रोक दीजिये, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्थगित कर देंगे, इस तरीके से बात नहीं हो सकती है । चलिये, मा0 सदस्य नेमतुल्लाह जी आप पूरक पूछिये ।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय, माननीय मंत्री जी जो स्मार्ट मंत्री है, स्मार्ट हॉस्पिटल के लिए जो इन्होंने एलान किया था दरौली का, बरौली का, यानि कई हॉस्पिटलों का एलान किया था कि उसको स्मार्ट हॉस्पिटल बनायेगे लेकिन अभी जवाब आया कि नहीं, इसतरह की कोई बात नही है, उत्तर अस्वीकारात्मक है, तो ठीक है लेकिन उसको उत्क्रमित सामुदायिक हॉस्पिटल बनाने की बात जो कही है और वहॉ पर जमीन भी उपलब्ध है, इन्होंने कहा कि न्यायालय में रिकोमेंड भी किया है वहॉ के डी.एम. साहब ने, तो ये कब तक इसका निष्पादित करके कब तक काम शुरु करायेंगे, ये सामुदायिक हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया को ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है, विभाग के तरफ से प्रयास होता है और विभाग के तरफ से प्रयास हो रहा है,मेरे गृह जिला के बगल का जिला है इसलिए मेरा विशेष ध्यान रहता है बरौली विधान सभा पर .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय, अतिरिक्त जमीन है और भी जमीन हॉस्पिटल को ऑलरेडी उपलब्ध है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है तो माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिये ।

श्री भोला यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इसतरह का मामला वैशाली में जो खुला है मेडिकल कॉलेज महुआ में, सबसे शुरु में इसका घोषणा हुआ, कार्य भी शुरु हुआ लेकिन माननीय मंत्री जी लगता है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसके चलते यह अस्पताल अभी तक मूर्त रुप नहीं लिया है तो यह कब तक अस्पताल मूर्त रुप लेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मैं उसपर भी बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न भोला बाबू ने उठाया है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, काम भी चल रहा है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 408 (श्री नौशाद आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, प्रश्न में वर्णित गॉव के टोले में 10-12 घरों की विद्युत आपूर्ति को बगल के स्थानीय टोलों के निवासियों द्वारा अस्थायी रुप से बाधित किया गया था, अवरोध को दूर करते हुए उक्त टोलों में 10-12 घरों की विद्युत आपूर्ति को पुन: बहाल कर दी गयी है ।

श्री नौशाद आलम: धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 409 (श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 3: मधेपुरा जिलान्तर्गत बाबा मेंही दास की जन्मस्थली को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किये जाने के बिन्दु पर निर्णय मधेपुरा जिलान्तर्गत अन्य पर्यटकीय स्थलों को विकसित किये जाने की प्राथमिकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, बाबा महर्षि में ही दास जी को सब लोग जानते होंगे और हमारे ही क्षेत्र में उनका जन्मस्थली है मझुंआ गॉव में और कुप्पाघाट भागलपुर को भी हमारे सदन के माननीय सदस्यगण जानते होंगे । कुप्पाघाट भी बाबा महर्षि के नाम से ही प्रख्यात हुआ था, तो सरकार का जवाब सकारात्मक है । हम आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी, जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है, को धन्यवाद देता हूँ तथा आभार प्रकट करता हूँ ।

टर्न-5/सत्येन्द्र/28-02-2020

तारांकित प्रश्न संख्या-410(श्री नीरज कुमार)

अध्यक्ष: उत्तर दिया हुआ है, देखे हैं?

श्री नीरज कुमार: जी नहीं देखे हैं ।

अध्यक्ष: पढ़ दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, सर्वाराम दियारा के वासियों द्वारा यह बताया गया कि गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में आये बाढ़ से भूमि कटाव के कारण अन्यत्र स्थान से पलायन होकर उक्त स्थान पर बसे हैं। सर्वाराम दियारा में अलग अलग स्थानों पर बसे हैं जिनको ग्रिड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति देना संभव नहीं है। उनको वैकल्पिक सौर ऊर्जा के माध्यम से ही बिजली आपूर्ति की जा सकती है। वर्तमान में योजना(डी0डी0जी0)का कार्य सम्पन्न हो चुका है। इस विशेष परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के आलोक में इस कार्य हेतु नई योजना बनाते हुए कार्य कराने का लक्ष्य अप्रैल, 2020 है। जौनिया दियारा में लगभग 25 परिवार पूर्व से बसे थे जिनको गैर परम्परागत सौर ऊर्जा डी0डी0जी0 योजनान्तर्गत (15 किलो वाट)मिनी ग्रिड प्लांट के माध्यम से विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या-411(श्री कमरूल होदा)

अध्यक्षः यह तो आपका पहला प्रश्न आया है न ?

श्री कमरूल होदाः नहीं, इससे पहले भी पहला प्रश्न था।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः महोदय, 1-स्वीकारात्मक है।

2-स्वीकारात्मक है।

3- वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, छतरगाछ निर्माण योग्य है । उक्त भवन की स्थिति का आकलन निगम के अभियंता से कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आकलन के पश्चात् भवन के जीर्णोद्धार अथवा नवनिर्माण कराने का निर्णय विहित प्रक्रियानुसार लिया जायेगा।

श्री कमरूल होदाः कबतक इसका पुनर्निर्माण कर दिया जायेगा?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः कॉरपोरेशन से रिपोर्ट मांगी गयी है और ये मानता है विभाग कि वह पुनर्निर्माण योग्य है, इसलिए उसको बनाया जायेगा । रिपोर्ट यथाशीघ्र प्राप्त करके उसको हम करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 412(श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 413(श्री ललन पासवान)

अध्यक्षः उत्तर दिया हुआ है ललन जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, इसमें इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, सुपरिंटेन्डेंट इंजीनियर को आदेश दिया गया है, जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट आने के बाद अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 414(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तुरकौलिया प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मथुरापुर को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। शीघ्र ही भवन का जीर्णोद्धार करते हुए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा । यहां से मात्र 15 कि0मी0 की दूरी पर ही 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुरकौलिया कार्यरत है। अतएव स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मथुरापुर को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार: महोदय,माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है पिछले सेसन में ही मेरे द्वारा सवाल लाया गया था जो विभाग को भेजा गया और सदर हॉस्पीटल को भेजा गया जांच प्रतिवेदन भेजने के लिए लेकिन वह अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। निर्णय आप लेते हैं और निर्णय लिया गया, पांच वर्षों से लगातार निर्णय आ रहा है सामने लेकिन अभी तक जो कार्य होना चाहिए उसके उत्क्रमण के संदर्भ में वह नहीं हुआ तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि जो 15 और 16 कि0मी0 की दूरी तय कर के वहां के गरीब जाते हैं इलाज कराने और हालात ये है महोदय, मैं उसकी व्यथा बतला रहा हूँ, वह मेरे घर के सामने है, मात्र एक अंधी ए0एन0एम0 के अलावा दूसरा कोई वहां नहीं है, वहां न दवा रहता है न कोई स्टाफ है । वहां से 15 कि0मी0 की दूरी पर बड़ा हॉस्पीटल है और वहां के गरीब जाते हैं तबतक दम तोड़ देते हैं। निर्णय तो पहले ही लिया गया था इसलिए माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि कबतक उसको उत्क्रमित करके बनाने का काम करेंगे?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: महोदय,मैंने अपने जवाब में बताया है कि उसके विकास का निर्णय हम सब लोगों ने उसके विकसित करने का निर्णय लिया है जो पी0एच0सी0 है आयुष्मान भारत योजना के तहत उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में हम डेवलप करेंगे । वहां 12 तरह की सुविधाएं आमजनों को दी जायेंगी । उसके लिए अलग से 17 लाख रू0 की राशि का उपबंध किया जाता है और वहां पर अलग से उपकरण इत्यादि खरीदे जाते हैं और यह काम अगले तीन माह में हम कर लेंगे । यह मैंने जवाब में बताया है कि उक्त सेंटर को हम हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर के रूप में आयुष्मान भारत योजना के तहत विकसित कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 415(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

अध्यक्षः आपका भी उत्तर दिया हुआ है, पढ़े हैं ?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : जी ।

अध्यक्षः तो पूरक पूछिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक है। दिनांक 26-9-19 तक कैम्प लगाकर कृषि विद्युत संबंध हेतु आवेदन प्राप्त किया गया था एवं 26-9-19 तक प्राप्त कुल आवेदन के निष्पादन का लक्ष्य दिसम्बर, 2019 तक रखा गया था। वर्तमान में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना द्वारा सुविधा एप के माध्यम से सभी श्रेणी के विद्युत संबंध हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है ।

2-अस्वीकारात्मक है। ऑनलाईन आवेदन सुविधा एप के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर विधान-सभा क्षेत्र में कितने किसानों के द्वारा कृषि फीडर का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह प्रक्रिया जारी है और 26-9-19 तक जो भी आवेदन दिये गये थे, अखबार में भी दिया गया था, फर्स्ट फेज में एक लाख, चालीस हजार बैयालीस हजार जो भी हो वह संख्या के अनुसार दे दिया गया है। अब यह कंटीन्यूअस प्रोसेस के तहत ऑनलाईन आवेदन लिये जा रहे हैं और आगे इसके लिए भी कार्रवाई चालू हैं, अगले माह से काम प्रारम्भ किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 416(श्री कुमार सर्वजीत)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 417(श्री हरिनारायण सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः1-उत्तर स्वीकारात्मक है।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्री ज्ञानेन्द्र शेखर, डी0पी0एम0 जिला स्वास्थ्य समिति, नालंदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित जिला सम्वर्ग के पदाधिकारी हैं । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा

पर नियोजित पदाधिकारी या कर्मचारी का पदस्थापन अवधि विशेष के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में कोई नीति नहीं है।

3–उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 418(श्री अभय कुमार सिन्हा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या– 419(श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या– 420(श्रीमती एज्या यादव)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड स्थित दक्षिणी धमौन पंचायत में कालीस्थान पोखर के नजदीक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है जो अपने भवन में संचालित है जिसकी आंशिक मरम्मति की आवश्यकता है। विहित प्रक्रिया अनुसार जीर्णोद्धार का कार्य कराया जायेगा। वहां टीकाकरण सहित अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

श्रीमती एज्या यादव: वहां का जो भवन है, वह ऑलमोस्ट टूटा हुआ है । ये जो मरम्मति है उसको कबतक करा दिया जायेगा यही मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: मैने कहा कि शीघ्र उसको करा लेंगे । बी0एम0आई0सी0एल0 को निर्देशित किया गया है । माननीय सदस्या को संज्ञान में होगा कि ये काम कॉरपोरेशन के माध्यम से होता है और उसको निर्देश दिया गया है और हम भी मान रहे हैं कि उसके जीर्णोद्धार की जरूरत है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 421(श्री जनार्दन मांझी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अन्तर्गत जेठौर नाथ मंदिर, अमरपुर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2014–15 में राशि एक करोड़ दो लाख सात हजार एक सौ सतरह रू0 की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत यात्री निवास निर्माण, चाहरदिवारी गेट एवं सोलर लाईट निर्माण का प्रावधान है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से दिनांक 17–1–20 को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 422(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री: महोदय, जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदन अनुसार सुपौल जिला अन्तर्गत किशनपुर प्रखंड के कोशी नदी के दोनों तटबंधों के बीच अवस्थित ग्राम पंचायत बौरहा अन्तर्गत 1593 पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान जी0आर0 आपदा

पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है । शेष जांचोपरांत सही पाये गये कुल 492 परिवारों को भी दिनांक 27-2-20 को जी0आर0 भुगतान कर दिया गया है।

टर्न-6/मधुप-हेमंत/28.02.2020

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 423 (श्रीमती एज्या यादव)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटोरी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-शिउरा स्थित ''अमर सिंह स्थान'' पर मेला चैत्र नवरात्रि में लगता है । दूसरी बार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है ।

मेले के स्वरूप एवं मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता के बिन्दु पर जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

श्रीमती एज्या यादव : इसका जवाब क्या समझा जाय ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : प्रतिवेदन की मॉग की गई है, जो सुविधा देनी होगी, प्रतिवेदन आयेगा, उसके बाद कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : वैसे यह बात सही है मंत्री जी, कि यह ''बाबा अमर सिंह'' का स्थान काफी प्रसिद्ध है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 424 (श्री गुलाब यादव)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखण्ड के काको पंचायत में अनिल स्मारक अस्पताल में संविदा नियोजित डॉ0 नन्दन ठाकुर, आयुष चिकित्सक पदस्थापित हैं ।

राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों की कमी है । इस कमी को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है जिसके आलोक में काउंसलिंग का काम चल रहा है ।

आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

जिस अस्पताल के बारे में माननीय सदस्य के द्वारा चर्चा की गयी है, वहाँ भी आवश्यकतानुसार जैसे ही हमें चिकित्सक उपलब्ध होंगे, हम पोस्टिंग कर देंगे ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, ये लोग जय श्रीराम का नारा लगाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में हनुमान जी का बसेरा है, हनुमान जी ही इलाज करते हैं पूरे हॉस्पिटल में, पूरा बंदर का वहाँ जमावड़ा रहता है । इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, सब कुछ है, वहाँ डॉक्टर की सुविधा ही नहीं है । मंत्री जी से पूरक प्रश्न भी है कि झंझारपुर का मेडिकल कॉलेज कब शुरू होने वाला है, सबसे पहले स्वीकृति हुई थी ? जय श्रीराम का नारा लगाते हैं तो वही हॉस्पिटल में इलाज करेंगे क्या?

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए न ।

श्री गुलाब यादव : वही तो बोले कि कबतक हो जायेगा, बताने की कृपा करें मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि वहाँ पर नन्दन ठाकुर, आयुष चिकित्सक पदस्थापित हैं, नया चिकित्सक उपलब्ध होने पर वहाँ हो जायेगा ।

झंझारपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में उन्होंने पूछा, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि टेन्डर हो चुका है, टेन्डर की प्रक्रिया अंतिम स्थिति में है, मुझे अंदाज है कि एक महीने के अन्दर टेन्डर निष्पादित हो जायेगा, उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।

तीसरी बात, जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ राम जी भी होंगे और जहाँ राम जी होंगे वहाँ हनुमान जी भी होंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 425 (श्रीमती समता देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड बाराचट्टी में ग्रीड एवं इससे संबंधित ट्रांसमिशन लाईन निर्माण की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जल्द ही इसको प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

श्रीमती समता देवी : नहीं समझे सर ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रक्रिया में है, जल्दी कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : जल्द करा दिया जायेगा ।

श्रीमती समता देवी : ठीक है, सर ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 426 (डॉ0 रंजू गीता)

अध्यक्ष : डॉ0 रंजू गीता ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 427 (श्री अशोक कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-224)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पंचायत बलिगांव के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, खंडवा भूमि के अभाव में निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रफीगंज अवस्थित है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र, खंडवा के भवन निर्माण हेतु समाहर्त्ता, औरंगाबाद को भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 428 (श्री बशिष्ठ सिंह)

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मंत्री : महोदय, अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

श्री बशिष्ठ सिंह : धन्यवाद है, महोदय लेकिन एक छोटा-सा सुझाव है.....

अध्यक्ष : लेकिन में तो अगला सवाल आ जायेगा ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, जो आपदा की राशि है, हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से, तत्काल उनलोगों को मिल जाय । एक-एक साल, छः महीना पर पैसा जा रहा है, हम विभाग से चाहेंगे कि अगर इस तरह की दुर्घटना सामूहिक हो गई तो तत्काल पैसा मिल जाय । क्वेश्चन करने पर डेढ़-डेढ़ साल का पैसा गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मेरे यहाँ का तकरीबन.....

अध्यक्ष : अलग से लिखकर सूचना दीजिएगा तब न !

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, 24 घंटा में पेमेन्ट करना है, 24 घंटा के अंदर पेमेन्ट करना है.....

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-429, श्री सूबेदार दास ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या- 429 (श्री सूबेदार दास)

अध्यक्ष : श्री सूबेदार दास ।

(माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 430 (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-221)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, नवीनगर, औरंगाबाद में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद के विरुद्ध सम्प्रति 1 नियमित तथा 3 संविदा नियोजित चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं । विशेषज्ञ चिकित्सक के सभी पद रिक्त हैं ।

औरंगाबाद जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारूण में चिकित्सकों के 13 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध सम्प्रति 05 नियमित चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं।

राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों की कमी है । इस कमी को दूर करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अनुशंसा भेजी गई है, जिसके तहत काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर वहॉ पर पोस्टिंग कर दिया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय.....

अध्यक्ष : पूरक भी है ! अब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि महिला चिकित्सक की पदस्थापना नवीनगर में कर देंगे क्या ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : बिल्कुल । विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी नियुक्ति होनी है, तो वह भी होगा।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, सदन पटल पर रख दिए जाएं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 28 फरवरी, 2020 के लिए माननीय सदस्यगण सर्वश्री महबूब आलम, अब्दुल बारी सिद्दिकी, रामदेव राय, ललित कुमार यादव, सुदामा प्रसाद एवं समीर कुमार महासेठ से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-171(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री महबूब आलम : महोदय.....

अध्यक्ष : आप तो बोल चुके हैं तो फिर अब क्या बोल रहे हैं । शून्यकाल सबका पढ़वाना है।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पटना में कल सातवीं की छात्रा को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया है । यही बिहार का सुशासन है, महोदय ? सरकार का यही न्याय के साथ विकास है ?

महोदय, सरकार को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए । अभी तक 24 घंटा होने जा रहा है, अभी तक बच्ची का कोई अता-पता नहीं है । सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोयी हुई है । इसमें अविलंब कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष : आप सदन पटल पर रख दीजिए, सरकार संज्ञान लेगी ।

शून्यकाल । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

शून्यकाल

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के शेरघाटी थानान्तर्गत दिनांक-14.09.2018 को दुर्घटनाग्रस्त रंजीत कुमार, पिता-चन्द्रदेव यादव, ग्राम-कचौड़ी की मृत्यु दिनांक-24.09.2018 को हो गई थी, जिसका काण्ड सं0-536/18 शेरघाटी थाना में दर्ज है । आपदा प्रबन्धन विभाग से मृतक के परिजनों को मुआवजा भुगतान की माँग सरकार से करता हूँ ।

टर्न–7/आजाद/28.02.2020

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पिपरा विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण पूर्वी चम्पारण जिला में दिनांक 25.02.2020 को ओलावृष्टि होने से किसानों के फसलों एवं जानमाल की भारी क्षति हुई है ।

अत: क्षति का आकलन कराकर किसानों को अविलम्ब मुआवजा दिया जाय।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सदर अस्पताल में .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट बैठिए । क्या बात है ?

श्रीमती एज्या यादव : महोदय, राज्य में एक बच्ची सुरक्षित नहीं है ....

अध्यक्ष : आप माईक पर बोलिए ।

श्रीमती एज्या यादव : महोदय, जब राज्य में बच्ची सुरक्षित नहीं है, 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है .....

अध्यक्ष : किस मामले पर बोल रहे हैं ?

श्रीमती एज्या यादव : सर, लड़की की सुरक्षा के मामले पर, महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर.....

अध्यक्ष : उसपर तो बात हो गई । सदन पटल पर रख दिये, सरकार उसपर संज्ञान लेगी । अब तो आप ही लोगों का है शून्य काल ।

श्री मो0 नवाज आलम ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सदर अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन की कमी है । दुर्घटनाग्रस्त होने पर लोगों को पटना जाने में रास्ते में मृत्यु हो जाती है ।

अत: आरा सदर अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन की नियुक्ति की जाय।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, विकसित तकनीक से बनने वाली गाड़ियों में स्पीड अधिक रहने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है । मधुबनी में ट्रामा सेंटर नहीं रहने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को दरभंगा, पटना ले जाने में मृत्यु हो जाती है ।

अतः मधुबनी में एक ट्रामा सेंटर बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, गृह अगलगी पर आपदा से मुआवजा का प्रावधान है परन्तु दुकानों में आग लगने पर मुआवजा का प्रावधान नहीं रहने से गरीब दुकानदार बेरोजगार हो जाते हैं ।

अतः छोटे दुकानों में आग लगने पर आपदा पीड़ित को मुआवजा राशि देने का प्रावधान बनाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के गन्ना किसान सामूहिक हत्या कर रहे हैं । मगध शूगर मिल, हसनपुर द्वारा गन्ना उचित मूल्य पर नहीं खरीदी जाती है । किसानों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है ।

सरकार गन्ना किसानों के हित में गन्ना क्रय केन्द्र, महेशखूँट को पुनः चालू करावें ।

श्री शत्रुधन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.02.2020 को राज्य में आये आँधी एवं बारिश के कारण सारण जिला के मकेर, परसा तथा अमनौर प्रखंडों में रब्बी एवं दलहन के फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुई है । मैं प्रभावित किसानों को क्षतिपूत्ति देने की मांग करता हूँ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड के मंजोस गांव के वरना नदी से टाल सहरसा तक नहर सफाई, खुदाई एवं मरम्मति कर टाल गांव को सिंचाई सुविधा दिलाने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के सोन उच्चस्तरीय नहर लॉजी से निकलने वाली तेलारी वितरणी में गाद भर जाने से निचले छोर तक पानी नहीं पहुँच पाता है । पटवन बाधित है, जनहित में वितरणी की सफाई कराने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, राज्य के जिला मधुबनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हायट नरार के प्राचार्य द्वारा डी0एल0एड सत्र 2019-21 में नामांकन हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया । जॉच में अनियमितता पाये जाने के बाद भी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं हुई । मैं दोषी प्राचार्य पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड के कोटवा थाना अन्तर्गत कझिया ग्राम के निवासी मजदूर प्रेमचन्द्र महतो उम्र 39 की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात से दिनांक 23.02.2020 को हो गई, ये काफी गरीब परिवार के हैं।

आश्रितों को उचित मुआवजा हेतु मांग करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, फारबिसगंज एवं नगर पंचायत, जोगबनी के वार्डों के ऐसे जमीन जो ग्रामीण एवं खेतीबारी से जुड़ा है, जिसका स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमीन की कीमत के अनुपात में ज्यादा है । जरूरतमंद जमीन खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं । ऐसे वार्डों की जमीन की प्रकृति सुधार कर शुल्क कम करने की मांग करता हूँ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कोशी नहर पर समाज के कमजोर वर्ग की एक बड़ी आबादी अस्थाई तौर पर रह रही है । उक्त परिवारों को खुले मैदान में शौच के लिए जाना पड़ता है जो एक कलंक है ।

अतः सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था करावें ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 20 सितम्बर, 2019 को रूपेश कुमार पिता- बाबूधन चौधरी और रजनीश कुमार पिता अयोध्या चौधरी दोनों ग्राम-पोस्ट-अन्हारी, थाना-चौंरी, जिला-भोजपुर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी । मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री शत्रुधन तिवारी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : आपकी सूचना पहले से पढ़ी हुई है ।

श्री शत्रुधन तिवारी : जी, सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गाँधी सेतु, राजेन्द्र गाँधी सेतु के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन बाधित होने को देखते हुए एवं आम आदमी को परेशानी के मद्देनजर विचारोपरान्त दिनांक 20.01.2019 को जे0पी0 सेतु से पटना से छपरा जाने के लिए एक तरफा भारी वाहनों को जाने की अनुमति थी । परिचालन की समय अवधि 10 बजे रात्रिकाल से 5 बजे सुबह तक निर्धारित की गई थी ताकि आमजनों एवं छोटे वाहनों के परिचालन में परेशानी नहीं हो । दिनांक 25.02.2020 को महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को पत्र द्वारा जे0पी0 सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन से पुल को होने

वाली क्षति एवं इससे उत्पन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है । मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संबंध में पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना, सारण, भोजपुर, वैशाली, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, पुलिस अधीक्षक, सारण, भोजपुर, वैशाली एवं पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को अविलम्ब जे0पी0 सेतु पर भारी वाहनों को तात्कालिक रूप से प्रतिबंधित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है तथा लगातार निगरानी रखते हुए समुचित यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आवागमन बाधित नहीं हो । इसको रोक दिया गया है ।

श्री शत्रुधन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, 22 नवम्बर, 2019 को जे0पी0 सेतु, दीघा पर भारी वाहनों के परिचालन की मंजूरी कुछ शर्त्तों के अधीन दी गई थी .....

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : इसको बंद कर दिया गया है ।

श्री शत्रुधन तिवारी : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बंद हो गया है ।

अब श्री भोला यादव एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना, श्री भोला यादव जी पढ़ें।

सर्वश्री भोला यादव, अब्दुलबारी सिद्दिकी एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, देश के कई राज्यों यथा आन्ध्र प्रदश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, प0बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों में राज्य के सरकारी नौकरियों एवं राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक लागू है । बिहार में अभी तक स्थानीय आरक्षण नीति लागू नहीं हुआ है जिसके कारण इस प्रदेश की सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी अधिकांश सीट पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि हमारे राज्य के बच्चे दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं ।

अतः बिहार राज्य के सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय आरक्षण 90 प्रतिशत लागू कराने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-8/शंभु/28.02.20

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : जवाब होने दीजिए न, सप्लीमेंट्री में पूछ लीजिएगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : ध्यानाकर्षण में जिनका हस्ताक्षर होता है वही पूछते हैं न ।

अध्यक्ष : चलिए, विशेष परिस्थिति में होता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार आरक्षण अधिनियम-3 (1992) यथा संशोधित अधिनियम-17/2003 द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला जो राज्य के मूल निवासियों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त बिहार अधिनियम-2(19) के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो इस राज्य के मूल निवासी हों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित किये गये हैं । इस प्रकार राज्य के मूल निवासियों के लिए कुल आरक्षण अनुपात 60 प्रतिशत है । महोदय, इसी प्रकार बिहार अधिनियम-16(2003) के द्वारा आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए जो राज्य के मूल निवासी हों, राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः, अंशतः सहायता प्राप्त सभी स्तर के सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं तथा बिहार अधिनियम-2(19) के द्वारा राज्य के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो इस राज्य के मूल निवासी हों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी है । इस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में 60 प्रतिशत सीटें राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित की गयी है । शेष 40 प्रतिशत की रिक्तियां सीटों के खुली गुण कोटि के आधार पर अभ्यर्थियों को भरने का प्रावधान रखा गया है । इस 40 प्रतिशत रिक्ति सीटों के विरूद्ध राज्य के अभ्यर्थी सहित अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी चयनित हो सकते हैं । इस प्रकार राज्य के मूल निवासियों को शत प्रतिशत रिक्तियां सीटों के विरूद्ध चयनित होने का

अवसर उपलब्ध होता है । उपर्युक्त के आलोक में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 90 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है । माननीय सदस्यगण को अवगत कराना चाहते हैं कि राज्य सरकार इस राज्य के मूल निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह जेनरल जो आरक्षण है उसको लेकर के ही जवाब दिया । हमारा स्पष्ट सवाल यह था कि डोमेशाइल जो कानून हैं क्योंकि और अनेक राज्यों में यहां तक तो झारखण्ड के राज्य ने भी पारित करने का काम किया, जो हमारा पड़ोसी राज्य है। वह 100 प्रतिशत । आप देखे होंगे जो बिहार के लोग हैं और सर्वे के हिसाब से 50 फीसदी पलायन बिहार में बढ़ गया, यानी बिहार का हर दूसरे घर के लोग पलायन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पलायन है वह रोजगार को लेकर है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार में जो बहुत रिक्तियां निकलती हैं जैसे बी. पी.एस.सी द्वारा चयनित प्रशासनिक, लोअर ज्यूडिशियरी हो या प्राध्यापक पद पर देखा गया है कि भारी संख्या बाहर के लोगों की है। यहां टैक्नीकली बहाली के लिए जो भी आवेदन निकलता है जो पद रिक्त हैं आप देखे होंगे कि बाहर के लोग ज्यादा हैं और यही हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो कई अन्य राज्यों में उन पर लाठी–डंडे भी बरसाने का काम किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो बेरोजगारी का केन्द्र बना हुआ है तो ये डोमेशाइल कानून हम लोगों की मांग है कि बिहार में लागू की जाए इससे बिहार का पलायन भी रूकेगा और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार भी मिलेगा।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय ऐसा है कि मैंने जो उत्तर दिया कि 60 प्रतिशत तो आरक्षण है ही राज्य के लोगों को बाकी मेरिट के आधार पर लोग आते हैं, ये बात ठीक है कि ज्यूडिशियरी में आरक्षण नहीं है, लेकिन अब बिहार पहला राज्य है जिसमें बहुत दिनों के बाद लोगों को ज्यूडिशियली जिलाा लेवेल में आरक्षण दे दिया गया है । अब जहां तक बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो जो आंकड़े हैं– गुजरात जो सम्पन्न राज्य है, अमेरिका में आज वहां के कितने लोग हैं, केरला, तमिलानाडू, दुनिया के हर मुल्क में हर राज्य के लोग जो सम्पन्न राज्य भी है नौकरियों के लिए स्वाभाविक है रोजगार करने के लिए लोग बाहर जाते हैं । इसे कैसे रोका जा सकता

है । दूसरी बात ये नागरिकता पूरे देश की है। ये भी एक सवाल है कि अगर हम लोग रोक देंगे तो और राज्य भी रोकेंगे तो फिर तो प्रोब्लम होगी ।

(व्यवधान)

आप लिख कर आंकड़े दीजिए कि कहां-कहां रोका गया है और कहां-कहां क्या है लिख कर दीजिए, सरकार इसपर गंभीरता से विचार करेगी ।

अध्यक्ष : लिखकर दे दीजिए सरकार को, अब तो हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार के जो सात करोड़ नौजवान हैं वे भगवान भरोसे हो गए । यानी सरकार यह कहना चाहती है कि वह पलायन रोकने में सक्षम नहीं है, रोजगार देने में सक्षम नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब अंतिम पूरक ।

श्री भोला यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो चयन हुआ है लेक्चरर के पद पर जिसमें अंग्रेजी सब्जेक्ट में 90 प्रतिशत एक प्रदेश केरला के आ गए हैं । आपसे पिछले सदन में जब हमने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया था तो आपने कहा था कि जल्द हम आरक्षण नीति लायेंगे, स्थानीय आरक्षण नीति लायेंगे, लेकिन वह समय भी छः महीने से अधिक हो गया है, क्या आप आरक्षण नीति लाने का विचार रखते हैं या इसी तरह राज्य की जनता को राज्य के छात्रों को परेशान होने के लिए छोड़ना चाहते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : पिछले सत्र में आपका और ललित जी वगैरह का ये था दरोगा और डीएसपी के मामले में उसको करेक्ट.....व्यवधान ।

(व्यवधान)

सुनिए आप जरा सुन तो लीजिए । अब ये दंत कथा में हम नहीं सकेंगे । चलिए बैठिए-बैठिए उसका उत्तर दे दिया गया है, आप सुनने को तैयार नहीं हैं । आप वकील के साथ रहे हैं तब भी इतने ज्ञानी नहीं हैं कि सदन में कैसे, सुना तो कीजिए पूरी बात । आप तो रामानन्द बाबू के साथ थे ना, वो काबिल वकील थे । आप बैठिए-बैठिए ।

अध्यक्ष : विजेन्द्र बाबू, ज्ञानी होने के लिए वकील के साथ रहना जरूरी नहीं है और बिहार की जनता ज्ञानी लोगों को देखकर, समझकर तब ही यहां लोगों को भेजती है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : लेकिन, भोला बाबू का मैं आदर करता हूं कि वकील कानून के, संविधान के ज्यादा जानकार माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उनके साथ रहने पर और ज्यादा जानते हैं । महोदय, जहां तक ये प्रोफेसर वाला है अलग से सवाल कीजिए, इसको भी देखवायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : आपको याद होगा जब हम डिप्टी सीएम थे माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी ने इस बात को रखा था बड़े जोर-शोर से कि डोमेशाइल कानून लागू होना चाहिए, लेकिन उस समय हमलोग ठगा गये । हम इतना चाहते हैं सरकार के लोगों से कि कम से कम हमलोगों को ठगे ठीक है लेकिन 7 करोड़ नौजवानों को मत ठगना ।

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद एवं अन्य सूचना पढ़िए ।

सर्वश्री तारकिशोर प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, राज्य में कृषि विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर कृषि प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राज्यादेश संख्या-1304, दिनांक-08.08.2010 के आलोक में किसान सलाहकारों का नियोजन किया गया है । इनके कठिन परिश्रम से विभागीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में मदद मिली है । ये दस वर्षों से नियमित कर्मी की भाँति तकनीकी एवं गैर तकनीकी योजनाओं का कार्यान्वयन करते आ रहे हैं । इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य यथा जनगणना, पशुगणना, चुनाव कार्य, विधि व्यवस्था, राशन कूपन वितरण, ऑनलाइन क्रौप कटिंग, फसल सहायता सत्यापन, धान अधिप्राप्ति, सात निश्चय एवं जल जीवन हरियाली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन भी करते हैं ।

अतः किसान सलाहकारों को पंचायत स्तरीय कृषि प्रसार संविदा कर्मी के रूप में मान्यता देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-9/28-02-2020/ज्योति-मुकुल

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : 19 मार्च को जवाब देंगे, होली के बाद ।

अध्यक्ष : मतलब कुछ शुभ सूचना दीजियेगा क्या ? होली के बाद इसको लिस्ट किया जायेगा । माननीय मंत्री, उर्जा विभाग ।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105(2) तथा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012 के नियम-5 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग का वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

(वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत ''बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019'' तथा ''बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–10 /कृष्ण/28.02.2020

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श का आज दूसरा दिन है, लगभग एक–सवा घंटे का समय उपलब्ध है, सरकार का उत्तर होगा और 4 बजे कार्यवाही समाप्त होगी । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने संभवतः 13वीं बार या 11वीं बार रेकर्ड कायम किया है इन्होंने । बजट भाषण इस सदन में पेश किया और इस बार तो क्या कहना, कहा गया ग्रीन बजट है । चलिये दिखता तो ग्रीन जरूर है । महोदय, अब कभी ग्रीन बजट हो जायेगा, कभी ब्लू बजट हो जायेगा, कभी रेड बजट हो जायेगा, नारा गढ़ने में तो महारथ हासिल किया है इन्होंने। महोदय, यह जो ग्रीन बजट है, मतलब जो यह कार्यक्रम है, जल–जीवन–हरियाली, इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और हमलोग बहुत पहले से इसकी मांग करते रहे हैं । मगर अब जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम जो चलायी जा रही है, उसका तो प्रचार–प्रसार तो हो रहा है बहुत । जगह–जगह फ्लैक्स लगे हुये हैं, जल–जीवन–हरियाली । महोदय, चूंकि हमारे वित्त मंत्री जी थोड़ा पढ़ते–लिखते हैं, गूगल्स सभी देखते हैं तो जो फ्लैक्स लगे हैं जगह–जगह तो इससे किस तरह का पर्यावरण सुधार रहे हैं । इसमें पी0बी0सी0 यूज होता है, जिसको एक तरह से स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक माना गया और नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने इसको कहा है कि इससे कैंसर होता है । अब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कम से कम इतनी तमीज तो होनी चाहिए थी कि जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम को जब हम लौंच कर रहे हैं तो उन चीजों को भी हम अपने में शामिल नहीं करेंगे, जिससे कहीं न कहीं यह कार्यक्रम प्रभावित होता है, मगर है तो बीमारी छपास की, बोर्डिंग की, होर्डिंग की, फ्लैक्स की । अब माननीय वित मंत्री अलग से बता देंगे कि फ्लैक्स में सरकार ने कितना खर्च किया और क्या यह फ्लैक्स यूज करना जन–जीवन–हरियाली कार्यक्रम का मजाक नहीं है तो और क्या है ? हम यह नहीं कहते कि इस योजना से हमारा कोई मतभेद है ।

अब महोदय, इनका हो बजट है 104 पेज का, पिछला वाला भी 104 पेज का था । इस में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और सत्तापक्ष के कुछ लोग मगर उनको लालू जी का भूत उतरता नहीं है और मुझको लगता है कि लालू जी का नाम नहीं लेंगे तो लगता है कि रोजी-रोटी चली जायेगी । रोजी-रोटी अब क्या जायेगी ? 11 साल से, 13 साल से बजट आप पेश कर रहे हैं । मगर आप ग्रीन बजट पेश करके ग्रीनरी माहौल बनाये हैं, कभी रोजी माहौल बनाईयेगा, कभी ब्लू माहौल बनाईयेगा । महोदय, यह कौन नहीं जानता, यह तो ऑन रेकर्ड है कि 2004 और 2005 में योजना का आकार क्या था और अभी योजना का आकार क्या है ? अच्छा होता, हमलोगों के आंदोलन के समय साथ ही रहे हैं, थोड़ा कद्र भी करते हैं, मगर जो शिक्षा-दीक्षा है, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता ।

महोदय, जब बिहार का 2005-05 के योजना आकार को आपने माईल स्टोन बनाया। जरा देखते कि मध्य प्रदेश का 2004-05 में कितना था, उत्तर प्रदेश का कितना था, महाराष्ट्र का कितना था, गुजरात का कितना था और जैसे अब आपका बढ़ा है, वैसे ही उनका, आप जो पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हमारा तो 2 लाख 11 हजार करोड़ हो गया । अब यह बताते कि इसमें आपका ओन सोर्स मोबलाईजेशन से कितना पैसा है और केन्द्र सरकार, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय सहायता से कुल कितनी राशि है । मोदी जी, आप याद कीजियेगा । हमलोगों की मिहनत से जो फाईनेन्स कमीशने ने, हमलोगों ने पहल की थी, उससे माननीय श्री विजेन्द्र बाबू भी थे, ऐज ऐ अपोजिशन, उस वक्त से फाईनेन्स कमीशन का रूख बदला और जब राशि आई तो आपको उपयोग करने का मौका मिला, हम चले आये ।

अब महोदय, कम से कम हमारे वित्त मंत्री जी जब पीठ थपथपाते हैं कि हमारा आकार इतना बढ़ा, इतना बढ़ा तो कम से कम किताब में यह भी जरूर दे देना चाहिए था । यह तो हमलोग मानते हैं कि बजट कोई बाजीगिरी नहीं है, आय-व्यय का लेखा-जोखा है । तो आपने आय-व्यय के लेखा-जोखा में इस बात का भी अगर उल्लेख कर देते कि वर्षवार कितना पैसा अनुमानित होता बजट, आप कहियेगा कि हमारा अनुमानित था । मगर मैं कहां से शुरू करूं ? मतलब 2005-06 से शुरू करूं या 2016-17 से शुरू करूं, या 2018, 2015 से शुरू करूं कि टोटल बजट प्रोविजन कितना था और एक्सपेंडिचर कितना हुआ ?

(व्यवधान)

1990 से कहियेगा तो 1090 से भी बता देंगे । 1090 वाला इनके पास है । आप अभी नहीं समझियेगा बजट, आप 90-90 कहते रहियेग ।

महादेय, 2004-05 से हमारे पास है जो कहते हैं कि 23000 या 24000 कुछ था । अब इनको जो मिला 2018-19 में मतलब टोटल प्रोविजन हो गया 2 लाख 17 हजार 378.6, एक्सपेंडिचर हुआ 1 लाख 54 हजार 655, लैप्स कहिये, व्यपगत कहिये या काम नहीं करने का, जो हो, जो व्यय हुआ 62,723.46 करोड़ । वैसे ही 2017-18 में इनका जो बजट का आकार था, उससे खर्च नहीं किया 57,174.67 और 2016-17 में इन्होंने खर्च नहीं किया 48,699.46 करोड़ और उसी तरह 2015-16 में 40,585.94 करोड़ इन्होंने खर्च नहीं किया । हां ठीक है । मेरा भी दे देते और आप अपना भी दे देते । महोदय, हमलोगों के यहां एक बहुत मशहूर कहानी है गांव का, सुनते होंगे । एक मुंशी था ।

अध्यक्ष : कहानी छोटी है कि लंबी है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : बहुत छोटी है ।

अध्यक्ष : आपका समय 30 मिनट का है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मेरा समय 40 मिनट का है । 40 मिनट हम ही बोलेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, बहुत छोटी-सी कहानी है । एक गांव में बड़ा शातिर मुंशी हुआ करता था । वह गांव वालों को परेशारन करके रखा था । किसी को इस केस में फंसाना, किसी को उस केस में फंसाना, किसी को कुछ करना, गांव पूरा उससे आजीज था । मगर जब उसके मरने का वक्त आया, तब भी उसने मरने के बाद भी अपना शातिरपन छोड़ा नहीं । उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मुझको लाठी लगाकर चौक पर खड़ा कर देना और हमलोगों का जो केस मुकदमा चलता है तो इसका-इसका नाम दे देना ।

क्रमश :

टर्न-11/राजेश/28.2.20

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: क्रमश: मतलब मरने के बाद भी अब खोलकर तो यहाँ बोलना ठीक नहीं है महोदय, लाठी लगाकर चौक पर कहा कि हमको खड़ा कर देना वही हाल महोदय, अरे मुंशीगिरी अब छोड़िये, आप वित्तमंत्री हैं, आप 1995,1996,1997,2004 एवं 2005 का रट छोड़िये, अब आपको 15 साल होने जा

रहा है, 15 साल में आपने क्या किया और क्या करने का विजन है, क्या कमी है, कैसे इस देश, इस राज्य को विकसित राज्य बनाइयेगा .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः मुंशी जी का हुआ क्या आखिर ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः मुंशी जी मर गए । उनको बांस लगा कर खड़ा किया और उसके बेटा ने कहा कि हमारे बाबूजी को फलां-फलां ने मार दिया । महोदय, अब जैसे जल, जीवन, हरियाली नारा गढ़ना तो कोई सीखे एन.डी.ए. सरकार से, शुरू से, बचपन से, आदत डाली जाती है कि ये झूठ बोलना, ये सच बोलना, ये बोलना, वो बोलना, ये नारा गढ़ना है, उसमें तो हम लोग फिट नहीं कर सकते । अब महोदय, जल, जीवन, हरियाली जो है, अब आप देख लीजिए पर्यावरण एवं वन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इसका जो 2019 और 2020 में जो इसके मद में है 357. 41 करोड़ और 2020-21 में है महोदय 440 करोड़ इसके मद में है और आप कह रहे हैं कि जल, जीवन, हरियाली के कार्यक्रम में 24,524 करोड़ रुपए हम व्यय करेंगे, मगर प्रावधान आपने क्या किया है ? प्रावधान किया है 6007.8 करोड़ और आप व्यय करते है 24,524, तब आप यह बताइये कि 24524 में अगर 6007 घटा दीजिए तो ये पैसा आपको कहां से आएगा ? इसका प्रबन्ध तो इन्होंने कर लिया होगा, इनके पास काबिलियत तो है, तो महोदय, मैंने मुंशी का जिक्र इसलिए किया था महोदय, मतलब कोई भी भाषण इनका हो चाहे 2005, 2004 या 1990 का भाषण हो, हर भाषण में चरवाहा विद्यालय की बात ये लोग करते थे और आज किताब में भी इन्होंने लिख दिया है चरवाहा विद्यालय, मगर सुशील जी विदेश भी घूमते हैं और मुझको लगता है कि शायद ये गये होंगे आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलिया गये होंगे, तो वहां एक सेफर्ट स्कूल इसी पैट्रर्न पर है, नहीं गए हो, तो एक बार पता तो कर लीजिएगा और महोदय, अब रही बात इन्होंने कहा कि हमारे टाइम में इतना मेडिकल कॉलेज खुला, इतना ये खुला, इतना वो खुला, हमारे टाइम में कहा कि सिर्फ चरवाहा विद्यालय 116 खुला, ये इन्होंने कहा, अरे भाई झूठ भी बोलिए तो थोड़ा बढ़िया से बोलिए, महोदय, यहां पर आपके बगल में बैठे हुए है विजेन्द्र यादव जी, नरेन्द्र यादव जी, अब इनसे जरा पूछिए कि बी0एन0मण्डल विश्वविद्यालय कब बना, किस सरकार ने बनाया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा किसने बनाया, वीर कुवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा किसने बनाया, मौलाना मजलूम हक विश्वविद्यालय किसने बनाया और बिहार यूनिवर्सिटी का नाम बदला था श्री

अम्बेडकर जी के नाम पर और विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग किसने बनाया, हमारे ख्याल से सिद्दू-कानू विश्वविद्यालय किसने बनाया, अब महोदय, हमारे ख्याल से हमारे वित्तमंत्री जी साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, अच्छे विद्यार्थी रहे है, साइंस ही कॉलेज में पढ़े थे ना, उस वक्त जो क्रीम लोग होते थे वे साइंस कॉलेज में जाते थे, पटना कॉलेज में जाते थे, अब जरा आप एक बार जाइये साइंस कॉलेज में, एक बार जाइये पटना कॉलेज में, एक बार जाइये आप बी0एन0कॉलेज और एक बार आप जाइये कोई भी लिडिंग कॉलेज में या अगर ओल्ड ब्वाइज होता होगा, तो उसमें जाइयेगा तो वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जायेगा कि आपके टाइम में 1990 में, 1995 में, 2004 में, 2005 में जो स्थिति थी, आज सुशासन के राज में, राम-राज में शिक्षा, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, आप तो सब छोड़ दीजिये, अब स्कूल में ले लीजिये, हम पटना की ही बात बताते हैं महोदय, पटना हाई स्कूल प्रीमियर इन्सटिच्यूशन हुआ करता था, राम मनोहर लोहिया स्कूल प्रीमियर इन्सटिच्यूशन हुआ करता था, जिला स्कूल हर जिले में प्रीमियर इन्सटिच्यूशन हुआ करता था, अब जरा वित्तमंत्री जी ये बता देते कि वहां कितने नियमित शिक्षक हैं और कितने अतिथि शिक्षक हैं, ये बता देते ? अब महोदय, मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट है, ये रूटीन बजट है, विजन और डायरेक्शन की सर्वदा कमी है, बिहार अभी-भी विकास के मामले में आसमान की तरफ देख रहा है, गरीबी अभी-भी देश में सबसे ज्यादा 80.60 परसेंट, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं वो बिहार में ही हैं, उद्योगों की क्या स्थिति है ? कितना बड़ा-बड़ा प्रोग्राम कराया, दारू भी पिलाया, बीयर भी पिलाया और जब मेघनाथ देसाई आए, वे भी बोले, आके बयान दिए कि अगर गांधी जी आज जिन्दा होते, तो हम उनको बीयर ऑफर करते, क्या हुआ उस सबमिट का, कितने उद्योग आए, कितने उद्योग लगे, अब आप कहियेगा, हमारे राज्य में तो सब भाग गया, तो आपके राज्य में कौन-कौन आए ? आपके राज्य में उद्योग बढ़ा है माफिया का, उद्योग बढ़ा है बिचौलिया का, उद्योग बढ़ा है मतलब कि जो चोरी करने वाले लोग हैं, उनका उद्योग बढ़ा है, अब अगर मैंने पहले भी इसी विधान सभा में कहा था महोदय, अब पटना में जितने बड़े-बड़े मकान बने हैं, आप सिर्फ इसका सर्वे करा दीजिए, अब जातीय गणना का तो हमलोगों ने सदन से पास करके भेज दिया, अब आप केवल पटना में जो लोग नियम-कायदा को ताक पर रखकर चार करोड़, पांच करोड़, दस करोड़ का जो मकान बनाए हैं, आप उनका खाली सर्वे करा के इस सदन में एक रिपोर्ट डाल

दीजिए, तब पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार इस राज्य में बढ़ा है या उस राज्य में बढ़ा है, अरे भाई उस राज्य में तो 24 हजार करोड़ ही था, आपके राज्य में तो 2 लाख 11 हजार करोड़ है, इसमें कहां-कहां, क्या-क्या पैसा जा रहा है महोदय, उसका जिक्र करना, मतलब यह है कि अब महोदय आप हमेशा कहते हैं कि 2004, 2005 अरे आपको कहना चाहिए था कि हमारा विजन 2020-21, 2021-22 या 2023-24 का ये है, हमारा विजन मतलब 2025 में जो होगा, उसमें हमारा ये होगा, आप स्वयं जानते हैं 2020-21 का बिहार बजट 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला बजट है, ये तो इतिहास आपने रचा, किन्तु मैं दावे से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री सहित 12 करोड़ बिहारी में से शायद ही किसी को ऐसा लगा हो कि इस बजट में बिहार को अगले दशक में विकसित राज्य बनाने का कोई ब्लू प्रिंट है ।

क्रमशः

टर्न-12/सत्येन्द्र/28-02-20

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी (क्रमशः): महोदय, बजट केवल आंकड़ों की बाजीगिरी नहीं है या केवल सत्ता पक्ष के अकेले का काम नहीं है, इसमें सब की भागीदारी जरूरी है परन्तु अफसोस है कि राज्य सरकार ने 21वीं सदी के दो दशक को काफी समय पहले बर्बाद कर दिया और अब एक दशक बचा है । अब तीसरे दशक के पहले बजट में दुरदर्शिता का अभाव है, यह तो रूटिन बजट है, चुनावी बजट भी इसको कह सकते हैं, हरियाली हो कीजिये, अच्छा है लेकिन आप जो 11 साल का फायनांस संभाले हैं, अपने 11 साल का जिस टर्म में आप वित्त मंत्री रहे हैं का हिसाब कौन देगा, अब्दुल बारी सिद्दिकी देगा दो साल का, 11 साल का, 15 साल का तो आप ही देंगे। महोदय, मुझको लगता है बहुत शांत स्वभाव के भी हैं मोदी जी और जो बजट इस बार इन्होंने पेश किया है उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह इनका फेयरवेल बजट है, अगर फेयरवेल बजट नहीं होता तो राज्य को 4-5 बिन्दु चुनकर, अपनी प्राथमिकता चुनकर जैसे केजरीवाल जी ने चुना शिक्षा । आप सत्ताधारी दल के लोगों से पूछिये न अकेले में, यहां पर नहीं बोलेंगे, अकेले में बुलाकर पूछिये कि स्कूल की क्या स्थिति है, कॉलेज की क्या स्थिति है, हेल्थ की क्या स्थिति है और इन्होंने कहा कि हमारे टाईम में इतना कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज बगैरह बगैरह । खुला तो अच्छी बात है, उसमें बहुत सारे प्राईवेट लोगों का भी है महोदय, बजट सुनते समय तो कभी कभी कंफूयजन जैसा लगता है महोदय,

2005 में बिहार की बागडोर आपने संभाला, ठीक है हमलोगों को जनता ने मेनडेट नहीं दिया, जनता ने आपको मेनडेट दिया और आपकी एन0डी0ए0 की सरकार बनी मगर जरा यह बतला दीजिये कि 2015 में जनता ने आपको मेनडेट इधर बैठने का दिया था कि उधर बैठने का दिया था, मगर आप तो जुगारू लाल हैं, दोनों जुगारू लाल हैं समझा कि नहीं, खैर मुख्यमंत्री जी तो इंजीनियरिंग पढ़ें हैं तो जुगारू टेक्नोलोजी के मास्टरपीस हैं, ये भी साईंस पढ़ें हैं कोई आदमी लोकतांत्रित व्यवस्था में मेनडेट का इस तरह से मजाक उड़ाये, महोदय, ये लिखते बजट में कि साहब हम मेनडेट बगैरह नहीं जानते हैं, सरकार जैसे चलाना हो वह हम चलाते हैं और चला कर के दिखला रहे हैं ।

(इस अवसर पर मा0 सभापति,श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने आसन ग्रहण किया) अब महोदय, पीछे का कितना दिन गाते रहियेगा, जब आपलोगों ने 2005 में बिहार की बागडोर संभाली तो कितना समय जनता से मांगा? क्या 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल कितना मांगा है, आप 2005 में हमारे खिलाफ जनता में गये, आपने कहा बिहार की जनता को कि हमको सत्ता दीजिये हम निजात दिला देंगे। क्या आपने निजात दिला दिया महोदय, जीरो-टॉलरेंस करप्सन में, हमसे मत पूछिये, सत्ताधारी दल के लोगों को बुला बुलाकर, विधायक को अकेले अकेले में पूछिये कि राज्य में करप्शन का क्या हाल है और जो विधायिका है, मैंने इस 15 साल में, एक भी ऐसा नहीं देखा इस हाउस में जिससे विधायक की गरिमा बरकरार रहती हो। महोदय, मुझे याद है उस वक्त लालू जी थे, इसी से कारोबार चलता है तो चलाते रहिये, महोदय, उस समय रामेश्वर चौरसिया यहां बी0जे0पी0 के एम0एल0ए0 थे किसी डी0एस0पी0 ने उनके साथ मिसविहैव किया था, उन्होंने सवाल उठाया, उस समय सुशील जी भी थे, उस पर लालू जी ने सदन की कमिटी बनायी और वहीं महोदय, ,एक पूर्व मंत्री, पूर्व एम0पी0 एम0एल0ए0 पीताम्बर पासवान फूट फूट कर रोता रहा लौबी में कि एस0डी0ओ0 ने मेरे साथ ऐसा किया, मगर आप तो नई व्यवस्था कायम करते हैं, वह पीताम्बर पासवान बेचारा अपने दिल में ही लेकर मर गया कि हम किस काम के हैं। देखिये एक दिन पीताम्बर पासवान के साथ यह हुआ, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, न मेरी है न आपकी और यह भी याद रखिये कि ये ज्यादा परमानेंट है इधर भी आप आईयेगा तो आप कोई वैसा मिसाल कायम नहीं कीजिये जिससे किसी को किसी तरह का नफरत चिढ़ पैदा हो। महोदय,13-14 साल तो कट गया और इस बजट से साबित हो गया महोदय कि यह सरकार

निरंकुश है। इस सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है सिर्फ खानापूर्त्ति होती है। सरकार ने कोई होमवर्क तक नहीं किया है और यह सरकार इतने साल से सत्ता में है किन्तु हर कुछ लाईन के बाद वही 2004 और 2005, सरकार को दुरगामी सुधारों का एक विजन होना चाहिए। बजट में अब छोड़िये, आप कहां हैं, आप आज वहां हैं कल यहां होंगे और जो कल यहां है कल वहां होंगे, ये तो राजनीति में होते रहता है। आज आप वहां है कल यहां आयेंगे, आज हम यहां हैं कल उधर जायेंगे, अब यह अच्छा नहीं लगता है। अरे, हमने सपना में भी नहीं सोचा था कि 2015 से 20 तक में हम आ जायेंगे इधर और जिसको बैठाया जनता ने इधर, वह चला जायेगा उधर । होता है महोदय, अब महोदय,आपके बजट भाषण के एक एक पहलु को याद दिलाकर आपसे एक्सक्यूटिव एकाउंटब्लिटी मागूंगा हर दावे का एभीडेंस के साथ, मैं आपको दूंगा एक्सपोज करने के लिए, आपने कमेंट में अपने तीन प्वायंट का जिक्र किया, बजट के आंकड़े बजट की प्रक्रिया में सुधार और बजट का आकार, विकास की बात जब भी होती है आप बोलते हैं 2004 और 2005, आपके हवा-वाजी द्वारा निर्मित विकास के गुब्बारे वाली इमेज की हवा निकल गयी है। निकलती नहीं तो दिल्ली में, झारखंड में यह सब होता । महोदय, आपका रिपोर्ट कार्ड बतला देता हूँ, महोदय, अब जैसे ये कहते हैं कि हम तो सबसे ऊपर हैं, अरे, आप इसी में दिये रहते कि हमारा इतना सूचकांक पर है, केरल इतना पर है, छतीसगढ़ इतना पर है, झारखंड इतना पर है, कर्नाटक इतना पर है मगर यह बाजीगिरी, महोदय, केरल ने 70 के स्कोर के साथ सस्टनेबुल डेवलपमेंट इंडेक्स में पहली रैंक हासिल किया है,अब आप सस्टनेबुल इंडेक्स में कहां हैं ये आप बतलाईए महोदय, अब महोदय, एक चीज मैं भूल गया, आज कल जी0डी0पी0 उतर गया है और इस बजट में जेनेऊन प्रोग्रेस इंडीकेटर (जी0पी0आई0) का इस्तेमाल नहीं कर दिग्भ्रमित किया जाता है।(क्रमशः)

टर्न-13/मधुप-हेमंत/28.02.2020

...क्रमशः...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एस0डी0आई0 को ही विकास का सही मानक माना जाता है । यू0एन0डी0पी0 यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार 23 अंकों की तालिका में आप किस पायदान पर हैं, यह तो आप अपने जवाब में बता दीजिएगा । इसलिए मैं उस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूँ ।

महोदय, केरल 70 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है । हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है । 2018 के बाद से सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट यू0पी0 का हुआ है जो 29वें स्थान से 23वें स्थान पर आ गया है । उड़ीसा 23वें से 15वें स्थान पर है । सिक्किम 15वें से 7वें स्थान पर है । भारत का एवरेज स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 60 हो गया है, औसत 3 प्वायंट पूरे देश का बढ़ा । जबकि बिहार ने 2018 में अपने स्कोर में 48 से केवल 2 प्वायंट जोड़ा है, 50 हुआ है और आखिरी स्थान पर रहा फिर भी, 50 के बाद भी आखिरी स्थान पर है । भारत सरकार की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको एक लम्बी छलांग लगाने की आवश्यकता है । उसके लिए प्रायोरिटी तय करके आपको बजट बनाने की जरूरत है न कि रुटीन बजट बनाने की जरूरत है ।

महोदय, यहाँ न चाहते हुए भी, जैसे कहते हैं कि बजट खूब छपा, बाप रे, सबका ख्याल रखा गया, फलाना रखा गया मगर अभी भारत सरकार का बजट आया था, तो जो बिहार सरकार की इकोनोमिक्स सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया थी और जो अखबारों में छपी थी, वह हम इनके अवलोकनार्थ रखते हैं । उन्होंने कहा - The budget has dissapointed Bihar. It may be argued that the scheme announced for agriculture and rural development will benefit the state at it does the other sub state of the country. But, we need to keep in mind that the state remains at the bottom on multiple indicators of socio-economic development. यह तो उन्होंने कहा है, इसको भी मान ही लेना चाहिए ।

महोदय, बिहार विकास के सभी पैमाने पर सबसे नीचे है । अब यह सच्चाई आप मानिए या नहीं मानिए मगर कितने दिन तक मैनेज्ड इमेज चलेगा और कितने दिन तक, अब क्या कहा जाय, आजकल तो कहता है गोदी मीडिया या कौन मीडिया, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं किसको कहता है और कौन गोदी है यह भी हम नहीं जानते हैं । मगर आज न कल इनको भी मजबूर होना पड़ेगा, कम्पेल होना पड़ेगा कि सच को छुपायें नहीं बल्कि उजागर करें । महोदय, अब आप बजट बनाते हैं, हमने सुना था कि अपने स्पोर्ट्स वाले को भी बुलाया प्री-बजट में राय के लिए। महोदय, बुलाया गया मगर जो आपके यहाँ का सिस्टम है या जो हमारा सिस्टम है, हमलोग मीटिंग कर लेते हैं चेम्बर के साथ, ट्रेडर्स के साथ, डिफरेंट इससे । दूसरे

राज्यों ने इसमें क्या किया, असम और उड़ीसा में पीपुल्स गाइड टु बजट, वह निकाला । हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में आम जनता से बजट में सुझाव आमंत्रित होते हैं । हिमाचल प्रदेश का अलग से पोर्टल है, उड़ीसा व्हाट्स-ऐप, एस0एम0एस0 पथ, ई-मेल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं । उत्तराखंड फेसबुक पेज के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं ।

महोदय, आप जैसे राय लेते हैं तो हम किसी पर एहसान थोड़े ही करते हैं, वह तो हमारी मदद करता है कि हमको क्या चाहिए । मगर महोदय, तीसरा किन्तु सबसे बड़ा प्रोपगंडा आपके बजट के आकार का है, जो हमने पहले कहा । आपने कहा 2004-05 में 23,885, 2019-20 में बढ़ गया, 8.39 गुणा ज्यादा हो गया, फिर 2019-20 में 8.78 यानी 8 गुणा बढ़ गया । अच्छी बात है । मीडिया को कितना गुमराह कीजिएगा। आज के टाईम में आपने जो लैप्स किया, जो घोटाले हैं, जो काम पूरा नहीं हो सका और जो स्टीमेट घोटाला है, बनना चाहिए कितना, हम कहते हैं कि नहीं भाई, बनाइए मगर ऐसा नहीं कि जो राशि आपको है, उस राशि में अगर आप करप्शन पर चेक लगाइये तो और काम हो सकता है । महोदय, 2000 के टाईम का स्टडी कीजिए, अब सब जगह जल्दी में बजट पेश होता है । कोई राज्य है जहाँ 31 मार्च के बाद होता हो ? हर राज्य में, यहाँ तक कि सेन्टर में सुधार हुआ है । अगर बताऊं कि देश का पहला बजट 15 अगस्त, 1947 में जानते हैं कितने का था, 171 करोड़ का था । 171 करोड़ का देश का बजट था 1947 में। तब आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि आपके टाईम में योजना का पैसा ही नहीं था, आकार नहीं था, यह इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया और अब क्या है । अब आप देख लीजिए । महोदय, एन0के0 सिंह साहब की अध्यक्षता में, जो फायनेंसियल कमीशन आता है, उसमें जो राज्य को पैसा मिलता है तो विपक्ष नहीं चाहता है कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले स्टेट इंटरेस्ट में ? हमलोग नहीं जाते हैं, हमलोग अपना पक्ष नहीं रखते हैं, जगदानंद सिंह से लेकर, विजेन्द्र यादव से लेकर, सबलोगों ने फायनेंसियल कमीशन के पास अपना पक्ष रखा था ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : समय हो गया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : बोल दीजिए महोदय, उसी हिसाब से बोलेंगे ।

महोदय, जिसके कारण, हमलोगों की एक तरह से संयुक्त मेहनत से वित्त आयोग से मिला 15 हजार करोड़ रूपया और 2019-20 में मिला 63,406 करोड़

रू0 और 2020-21 में 78,896 करोड़ मिलने की उम्मीद है । महोदय, 5 मिनट और बोलेंगे ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आपका टोटल सब समय हो गया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हमने पहले ही पूछ लिया, 5 मिनट और ।

महोदय, इस बार बजट 2.11 लाख करोड़ का । महोदय, एक-एक चीज जो कहते हैं, कहते हैं हमारा गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस । मगर गुड गवर्नेंस के 4-5 विभाग का ही हम आंकड़ा बता देते हैं कि एक महीना मार्च में सिर्फ कितना खर्च किया। 2019-20 के अब तक के खर्च का आंकड़ा नहीं बताये, 2019 में ग्रामीण कार्य विभाग, इनको बजट उपबंध था 94,959.7

...क्रमशः...

टर्न-14/आजाद/28.02.2020

.... क्रमशः ....

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : 2019 में ग्रामीण कार्य विभाग इनका बजट उपबंध था 949597 रू0 और खर्चा किया 68669.20रू0 यानी 7.23 प्रतिशत, गन्ना उद्योग विभाग खर्चा किया 25.49 प्रतिशत, पर्यटन विभाग 35.36 प्रतिशत, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 39. 21 प्रतिशत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 39.41 प्रतिशत, कृषि विभाग 41.12 प्रतिशत, आपदा प्रबंधन विभाग 44.76 प्रतिशत, मंत्रिमंडल सचिवालय 49.03 प्रतिशत इसी तरह है महोदय । अब महोदय स्टेट के लिए भी जरूरी है जानकारी, अब एकाऊन्टेंट जेनरल का जो रिपोर्ट है ए0सी0, डी0सी0 के बारे में, यह किसी से छिपा हुआ है ? वित्त मंत्री हैं, सृजन के मामले में और अवैध रूप से बैंकिग का संचालन, हम इसमें डिटेल्स में जाना नहीं चाहते हैं, वित्त मंत्री हैं, इनको पता नहीं चला, मगर ये उनके फंक्शन में जाते हैं, ये गये, शहनबाज साहेब गये, गिरीराज सिंह गये, अश्विनी चौबे जी गये, मुख्यमंत्री जी गये, सब गये । सृजन का निबंधन इस उद्देश्य से किया गया था कि सिर्फ सबौर पंचायत में महिलाओं के बीच सहकारिता की गतिविधि को लोकप्रिय बनायेंगे मगर समिति द्वारा बैंकिग सेवा के लिए आर0बी0आई0 में अप्लाई किया गया और न तो आर0बी0आई0 से इनको बैंकिग का प्रमिशन मिला । मगर जब प्रमिशन नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में .....

महोदय, खतम कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में डी0डी0सी0, डी0एम0 द्वारा ऐसे बैंकों में पैसा डिपोजिट करने का कैसे निर्णय लिया गया । स्वाभाविक रूप से डी0एम0, डी0डी0सी0 का आदेश था तो पैसा ब्लॉक के गोराडीह, जगदीशपुर,

पीरपैंती, सबौर, सन्हौला और लैंड एक्यूजिशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिला नजारत, डी0आर0डी0ए0 । महोदय, अब ये कहेंगे कि यह मामला तो सी0बी0आई0 को चला गया । महोदय, अगर ये सी0बी0आई0 चला गया तो आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते ।

महोदय, खाली एक मिनट से दो मिनट लगेगा । हम सिर्फ इनसे पूछना चाहते हैं कि साहेब राज्य में कुल कितनी वैकेंसी हैं, इसे राज्य की जनता और बेरोजगार युवा को अवगत करायें नम्बर-1 और उसके बाद आपने गवर्नमेंट के लेवल पर सृजन में इनवॉल्व लोगों के साथ क्या कार्रवाई की , नम्बर-3 अब जो है 156 बच्चे मरे हैं मुजफ्फरपुर में, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है और उसके बाद हमारे उस दिन थोड़ा तकलीफ भी हुआ और माया भी आया । इस बार तो बाढ़ नहीं थी, जल-जमाव था, इसमें हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे अरूण भाई, हमारे अरूण भाई को छोड़ दिये, आप चले आये, हमको तो खबर किये रहते तो हम ही पहुँचा देते । हम गये थे जाबिर साहेब के यहां ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, अगर आप मेरा प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दीजिए तो दे दें । प्रोसिडिंग्स का यह सब मेरा पार्ट बना दीजिए ।

महोदय, अब लास्ट ही कर रहे हैं, हम यह सब दे रहे हैं । मगर शिक्षा-दीक्षा जो होती है तो उसका असर अंतिम काल तक रहता है । इसी हाऊस में जब बहुत सारे लोग बी0जे0पी0 के लोग थे, हमने बजट पेश किया था, इन लोगों ने कहा कि बाप रे बाप मियां लोगों को इतना दे दिया, 873.19 करोड़, बोले थे न आपलोग इधर से, आपलोग रेकर्ड जाकर देख लीजिए ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, खत्म कर रहे हैं, इसको आपने घटाकर के कितना कर दिया 496 करोड़ , महोदय, नफरत की राजनीति, मानसिकता .....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव, जनता दल युनाईटेड।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : अब घबराईए मत, इस भूल में मत रहियेगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी और आसन के तरफ से आज बिहार सरकार के तरफ से पेश 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया गया है, मैं आप तमाम लोगों को और अपने क्षेत्र के लोगों का अभिनन्दन के साथ अपनी

बात की शुरूआत करना चाहता हूँ । महोदय, हमलोगों का जो बिहार का बजट है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार बजट पेश कर रहे हैं और सचमुच में हरियाली मिशन की तरह ग्रीन बजट जो बिहार का पेश किया गया है, उसका मैं अंत:मन से उसका समर्थन और स्वागत करता हूँ । महोदय, कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार के ही अंग माने जाते हैं, इसी सदन में लिखा हुआ है, बिहार का बेहतर बजट है, इसमें सबको अपने तरफ से सुझाव, सहमति और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको किया जाना चाहिए । महोदय, ठीक ही कहा गया है कि

जब भी दूसरों पर तबसेरा किया कीजिए,
सामने आईना जरूर रख लिया कीजिए ।

महोदय, हम जब किसी बात की चर्चा करते हैं तो मुझे जरूर अपने अंत:मन से पहले अपने आपको पूछ लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि हम कहने क्या जा रहे हैं । दूसरी बात है कि कहा गया है कि

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल ढूंढ़ा आपना, मुझसे बुरा न कोय ।

महोदय, सरकार का जो यह बजट है, वह बिल्कुल ड्रीम और ग्रीन बजट है, इसका बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है । उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है, वह बहुत लम्बा-चौड़ा है, मैं उस आंकड़े के जंजाल में पड़ना नहीं चाहता हूँ, चूँकि समय मेरा कम है, आंकड़ा जब हम पढ़ने लगेंगे तो हम आंकड़ों में ही फंस जायेंगे, चूँकि आंकड़ा सबको वितरित है, सभी लोग उस आंकड़े को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आंकड़ा जो बताता है कि जबसे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर संभाले हैं, उस समय से ही बिहार का पूर्णकालिक बजट पेश होने लगा । इसके पहले जो भी सरकारें आयी, जितने भी सरकारों ने काम किया, वोट एंड एकाऊंट के माध्यम से 4 महीना का बजट स्वीकृत करके और बाद में बजट को स्वीकृत कराते थे । महोदय, जितनी भी तारीफ की जाय इस बजट का, चारों तरफ चहुमुखी विकास का संकलन किया गया है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने संबोधन में बिहार के उत्तरोत्तर विकास के संबंध में बताया है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार की सरकार है, बिहार के जो

केबिनेट है, बिहार के सभी मंत्रियों ने अपने विभागवार जो बिहार में विकास का जो खाका खिंचने का और जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है,

..... क्रमशः .....

टर्न–15/शंभु/28.02.2020

श्री विनोद प्रसाद यादव : क्रमशः....मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ । महोदय, आज की तारीख में बिहार देश में एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। हमारे बहुत से प्रतिपक्ष के साथियों ने कहा कि उद्योग धंधे नहीं लगे, बिहार विकास में पिछड़ा हुआ है । महोदय, आजादी के बाद जो भी लोग सरकार में 2005 के पहले थे वे लोग अपने मन से पूछें कि बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ ? क्या बिहार में संसाधन जो आज आए उस समय उपलब्ध नहीं थे या उनमें इच्छाशक्ति की कमी थी निश्चित रूप से जब वे इन बातों पर मनन करेंगे तो लगेगा कि वही बिहार है जब हम झारखण्ड और बिहार एक थे, जो हमारा वित्तीय प्रबंधन था, वित्तीय स्थिति बेहतर थी उस समय और नवम्बर 2000 में जब विभाजन हुआ और बिहार के पास संसाधनों की कमी हो गयी तो बिहार के पास विकास के लिए कुछ बचा नहीं था, केवल इच्छाशक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का आज बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने जा रहा है और दूसरा कोई नहीं है । इसमें माननीय वित्त मंत्री जी का जो कुशल वित्तीय प्रबंधन रहा है वह विकास का एक नया आयाम है । जो लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे तो आजादी के बाद से जो हमारे यहां मिनरल्स थे, माइन्स थे इन सबों का अगर उपयोग होता बिहार में उद्योग के क्षेत्र में बड़ा ही एक क्रांतिकारी बदलाव होता, लेकिन लोगों ने क्या किया भाड़ा समानीकरण नीति लागू कर दिया । भाड़ा समानीकरण नीति में क्या हुआ कि आप जो भी माइन्स का चीज है उसको देश के किसी हिस्से में ले जाओ आपको पैसा समान लगेगा चाहे 5 कि0मी0 की दूरी पर ले जाओ या 500 कि0मी0 की दूरी पर ले जाओ पैसा समान भाड़ा लगेगा जिसके कारण हमारे राज्य के विकास का जो ग्रोथ रेट होता उसको रोक देने का काम किया महोदय । यह तो बताएं उनको सोचने की जरूरत है कि आपने ऐसी नीति ही क्यों बनाया जिससे बिहार के लोगों को दूसरे पर आश्रित होने के लिए मजबूर होना पड़ा । बिहार को आपने गरीब राज्य बनाने का संकल्प लिया था, आपकी तो नीति ही थी कि बिहार जो डेवलप प्रदेश था, जहां पर क्रांतिकारी लोग बसते हैं, जहां विजनरी लोग बसते हैं, जिनके

पास विजन है, ताकत है, सोच है, अगर इनको डेवलप कर दिया जायेगा तब बिहार देश ही नहीं पूरी दुनिया में अग्रणी राज्य हो जायेगा इसलिए बिहार को आपने पिछड़ा करके रखा । मैं आप तमाम लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में देखिए । पहले लोग कहते थे कि नदी के दो किनारे नहीं मिलते हैं, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने बतला दिया कि नदी के किनारे मिल सकते हैं और राज्य के सभी दिशाओं में जितनी भी नदियां हैं उसपर दोनों किनारे का पुल जोड़कर के उसमें कहानी को समाप्त कर देने का काम किया । यहां पर विजन की सरकार है एक सोच की सरकार है जिसका सोच है कि हम बिहार की जनता को देश के जो दूसरे राज्य की जनता है उनसे बेहतर संसाधन उपलब्ध करायेंगे । जो यहां पर हमारा संसाधन है उसका हम बेहतर ढंग से वित्तीय प्रबंधन करेंगे । वित्तीय प्रबंधन के बाद देखिए 2006 के पहले ग्रामीण सड़कों का क्या हाल था ? किसी भी माननीय सदस्य से उनके, सभी माननीय सदस्य यहां पर जानकार हैं, अनुभवी हैं, अगर वे अपने घर इलाके के बारे में सोचेंगे तो पहले वर्षा के दिनों में चप्पल जूते हाथ में लेकर घर जाना पड़ता होगा, लेकिन आज अगर मुसलाधार बारिश भी होते रहता है तो प्रत्येक गांव टोले तक चमचमाती कारें घर तक पहुंचती है । यह क्रांतिकारी बदलाव यहां की सरकार ने किया है । आप तो केवल इन बातों को उलझाकर के, लोगों को बड़गलाकर के बिहार की जनता को उसके रास्ते से भटका दें तो अब बिहार की जनता देश को रास्ता दिखाने लगी है । इसलिए अब बिहार की जनता भटकनेवाली नहीं है । बिहार की जो जनता है वह देश के लोगों से ज्यादा आइ0ए0एस0, आ0पी0एस0 जितनी भी सेवाओं में देखें तो उसमें संख्या ज्यादा किसकी है ? बिहार के लोगों की संख्या है । विदेशों में भी देखें तो बिहारी प्रतिभा ही जलवा बिखेर रही है । इसलिए हमारे बिहार के लोगों का मनोबल छोटा मत कीजिए । हमारे बिहार के लोगों का जो मन है, जो हौसला है उसको बुलंदी पर रखिये, उनकी जो आवाज है उसको कम करने की जरूरत नहीं है । हमारा पथ निर्माण विभाग- जितना भी बिहार के अंदर गांव में देख रहा हूँ 18 फीट चौड़ी सड़क हम बना रहे हैं, जबकि पहले शहरों में भी ऐसी सड़कें नहीं होती थी । यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की जो सोच है । अब आप कुछ भी कह लीजिएगा, गांव में जाइयेगा तो जो आदमी पहले पैदल जूते-चप्पल हाथ में लेकर के घर पहुंचता था और आज वह 18 फीट चौड़ी सड़क पर घर पहुंच रहा है तो क्या आपकी बात को मानेगा ? आप उसको

जीत सकते हैं तो केवल बिहार सरकार के काम की तारीफ करके और आपको भी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करने से कोई छोटा नहीं होता है । तारीफ करने से आपकी जो सोच है वह और बुलंद होगा, आपका विचार और ऊंचा होगा । अगर हम दिन को रात कहने लगेंगे तो कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा बल्कि हमारी बात को सुनकर वह हंसने के सिवा कुछ कह नहीं सकता है । इसलिए जो बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में.....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आपका 2 मिनट समय बचा है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में-अभी तो महोदय हमारा 15 मिनट हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि आपका समय है, ठीक है जितना समय सीमा है हम उसी में अपनी बातों को रखेंगे । महोदय, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए । शिक्षा के क्षेत्र में पहले प्रखंडों में एक उच्च विद्यालय हुआ करता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक पंचायतों में प्लस टू विद्यालय की स्थापना कर दी और 01.04.2020 से सभी पंचायतों में प्लस टू की पढ़ाई शुरू हो जायेगी । क्या इस बात से लोगों को भटका सकेंगे। यहां बैठे हुए एकाध ही खुशनसीब व्यक्ति होंगे जो 2-3 कि0मी0 पर अपने विद्यालय जाते होंगे, मैं भी 10 कि0मी0 साइकिल चलाकर के स्कूल जाता था। महोदय, आज जो बदलाव आया है, आज जो क्रांतिकारी बदलाव आया है बिहार के अंदर उसको आप मिटा नहीं सकते हैं । आप चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए । पहले अस्पतालों में कुत्ता बेड पर बैठा रहता था, लेकिन आज की तारीख में क्या है ? आज की तारीख में वहां पर सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर बैठते हैं और लोगों का इलाज करते हैं यह बदलता हुआ बिहार है महोदय । बिहार के जो लोग हैं वे अपनी प्रगति को बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं । बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के जो लोग हैं हर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसने मन बना लिया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को और रामबिलास पासवान जी का जो गठबंधन है इस गठबंधन को 2020 में अपार समर्थन देंगे, प्रचंड समर्थन देंगे ताकि जो बिहार के प्रगति की गाड़ी है कहीं पर हिचकोला नहीं खाये और वह सरपट आगे बढ़ता जाय। महोदय, आपका इशारा हो रहा है मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन मैं केवल एक बात सरकार से कहना चाहता हूँ सुझाव के रूप में केवल यह कहना चाहते हैं कि हमलोग सूखा प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हमलोगों के एरिया में जल स्तर काफी

नीचे चला जाता है और वहां पर पानी का संकट होता है । मैं चाहता हूँ कि सरकार की बालू उत्खनन की जो नीति है उसमें उस एरिया में....क्रमशः...

टर्न-16/28-02-2020/ज्योति-मुकुल

क्रमशः

श्री विनोद प्रसाद यादव : उस एरिया में महोदय, बालू उत्खनन में स्थानीय उपयोग के लिए ही केवल उत्खनन के अवसर दिए जायं, चूँकि बालू से जो एब्जौर्विंग क्षमता है पानी का वह बना रहे । इसके लिए बालू उत्खनन में केवल स्थानीय उपयोग के लिए करें। मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो विधायकों की राशि है, वह समय-सीमा में खर्च हो जाय । दूसरी बात हमलोग अब अगले साल चुनाव में जाने वाले हैं तो हमलोगों की विधायक मद की राशि है उसमें एन.ओ.सी. लेने की जो व्यवस्था है, उसको समाप्त कर दीजिये ताकि हम जल्दी से जल्दी योजनाओं को स्वीकृत कराके पूरा कर सकें । महोदय, मैं अंत में पक्ष-विपक्ष सभी लोगों से कहूँगा कि एक मुहिम भी ऐसा चलाया जाय जिसमें इन्सान को इन्सान बनाया जाय । '' जिसकी खुशबू से महक जाय पड़ोसी का भी घर । फुल इस किस्म का हर समय खिलाया जाय, मेरे दुख दर्द का तुझपर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझे भी न खाया जाय । जिस्म दो हो करके भी दिल एक हो, ऐसे मेरे आंसू तेरे पलको से उठाया जाय ।'' अब एक ऐसा मुहिम भी चलाया जाय जिसमें बिहार को अपने पुराने अन्तर्राष्ट्रीय गौरव का बनाया जाय । हम सब मिल कर एक ऐसा माहौल बनायें जिसमें बिहार को देश में विकसित राज्य बनाया जाय । जयहिंद, जय बिहार, जय श्री नीतीश कुमार ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, आपका समय 4 मिनट ।

श्री अजीत शर्मा : सबको बढ़ा के देते हैं और हमको घटाकर ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आपकी पार्टी की तरफ से ही समय दिया गया था ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, 2020-21 के बजट पर हम बोल रहे हैं । वित्त मंत्री जी चले गए, चूंकि जो यह बजट का पैसा आप जो खर्च करते हैं ये जनता की गाढ़ी कमाई से जो आप टैक्स के रूप में वसूलते हैं ।(व्यवधान) सर, टाईम बढ़वा दीजियेगा, फिर । श्रवण बाबू जी क्या अब मैं बोल सकता हूँ । आप बात करेंगे तो हम नहीं बोल पायेंगे । ये जो गाढ़ी कमाई से जो टैक्स के रूप में लेते हैं, आप

बजट के रूप में बनाकर के खर्च करते हैं विकास पर । वित्त मंत्री जी चले गये बड़ा आश्चर्य लगता है । टैक्स लेने के लिए जैसे जी.एस.टी. एक गरीब मध्यवर्गीय लोग किसान भाई या गरीब लोग रेस्टोरेंट में बेचारे शौक से खाने जाते हैं तो 5 परसेंट टैक्स जी.एस.टी. लेते हैं और वहीं अपनी बेटी, बहन या बच्चों का बर्थडे अगर मनाने जाते हैं और वही खाना किसी रूम में या हॉल में खाने जाते हैं तो जी. एस.टी. 18 परसेंट लिया जाता है और सरकार बात करती है गरीबों के उत्थान की । इस पर ध्यान देने की बात है, वित्त मंत्री जी चले गये, निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि 18 परसेंट उसी खाने पर लेते हो और 5 परसेंट उसी खाने पर लेते हो, ये बिल्कुल अन्याय है । दूसरी विकास की बात होती है । चूंकि समय कम है, इसलिए मैं भागलपुर का उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजनल ऑफिस होता था पिछले 40 वर्षों से, अभी भी है । लेकिन चूंकि साजिश के तहत वहाँ विकास बाधित हो चूंकि जो वहां किसान जो खेती करते हैं उनका कतरनी धान विश्व में जाना जाता है, रेशम उद्योग विश्व में जाना जाता है । अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ लगता है तो वहाँ पर लोग अंचल रिजनल ऑफिस जाकर अपना लोन सैंक्शन कराते हैं तो साजिश के तहत उसको भागलपुर से पूर्णिया ले जाने की बात हो रही है, इसलिए वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इसको रोकने की जरूरत है, चूंकि भागलपुर पुराना शहर है । उप राजधानी के लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया है, उसको वहीं रहने दिया जाय, ये आग्रह करते हैं ताकि विकास बाधित न हो सके । बहुत विकास की बातें हो रही थीं बजट में जो आप पैसा लगाते हैं, किसी विभाग में वह बहुत अच्छी बात है, इस बार बजट 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने बजट बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बनाया है लेकिन जो काम धरातल पर होना चाहिए, जिसपर कंट्रोल आपका होना चाहिए आप तो मंत्री महोदय पर कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन नीचे जो पदाधिकारी वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर जब धरातल पर देखियेगा और जब वहाँ की रिपोर्ट लीजियेगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाता है । जैसे मैं उदाहरणस्वरूप बताता हूँ कि हर घर में जल देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन बोल रहे थे । भागलपुर शहर में 11-10-2014 में 490 करोड़ का आपने पाईप-लाईन और घर में कनेक्शन देने हेतु पैसे दिये थे, वह खत्म होने की तारीख थी जून, 2019 । आजतक काम क्या हुआ उसका लेखा-जोखा मैं देता हूँ । 400 कि.मी. पाईप

बिछाना था और बिछा 175 कि.मी. अभी तक । 19 जल मिनार बनाने थे, 5 बना एक भी चालू नहीं । 68,182 घरों में हाउस कनेक्शन देना था, 11,015 घरों में कनेक्शन दिया गया, लेकिन उसमें भी पानी नहीं । आपको एक बात उसी शहर का और बतायेंगे जैसे हमलोगों को जनता चुनती है तो हमलोगों का कोष होता है यह सब लोगों के लिए है, लेकिन जो पार्षद चुने जाते हैं, कौन्सिलर चुने जाते हैं उनके लिए कोई कोष नहीं है । जब जनता उन्हें कोई काम कहती है तो वह नगर निगम में जाकर पदाधिकारियों का चेहरा देखते हैं और उनका कोई काम नहीं हो पाता है । आप दिल्ली, बम्बई में देख लीजिये सभी कौन्सिलरों का फंड होता है ताकि वह जनता का विकास कर सके । अगर हमलोगों का कोई कोष नहीं होगा तो आज जो बात कर रहे थे कि एन.ओ.सी. का शर्त नहीं होना चाहिए तो हम लोग भी कोई काम नहीं करा सकते हैं और जनता हमलोगों को पूछती भी नहीं, इसलिए दिल्ली औार बम्बई की तरह वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं आग्रह करना चाहूंगा उसका भी प्रावधान होना चहिए और 50-50 लाख प्रत्येक पार्षद को विकास के लिए कोष उनको देना चाहिए। दूसरी बात स्मार्ट सिटी भागलपुर 2015 में चयनित हुआ आज पैसे पड़े हैं, फंड पड़ा हुआ है और कोई काम धरातल पर नहीं हुआ यह भी सोचने की बात है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है । ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं भागलपुर में टाटा प्रोजेक्ट को मार्च, 2019 में काम एलौट हुआ पावर सब स्टेशन 6 बनाना था एक भी अभी तक नहीं बना । तार बदलने का काम 200 कि.मी. करना था, मात्र 20 कि.मी. हुआ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री अजीत शर्मा: सर एक मिनट सर । 2,000 ट्रांसफार्मर में क्षमता वृद्धि करना था लेकिन हुआ 22 । 150 एडीशनल ट्रांसफॉर्मर लगाना था एक भी नहीं लगा । जब कि सारा उपलब्ध है । पथ निर्माण में भी जाम से निजात दिलाने के लिए एन.एच. 80 और पी.डब्लू.डी. की जो सड़क है, उसका चौड़ीकरण करके और नगर निगम के द्वारा जो होर्डिंग लगाए गए हैं रोड पर जो 5-6 फीट अतिक्रमण किया गया है उस होर्डिंग को हटवाकर चौड़ीकरण करने की जरूरत है ताकि भागलपुर की जनता को जाम से निजात मिल सके ।

सभापति(श्री वीरन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार ।

श्री अजीत शर्मा : सर, आपने तीन ही मिनट दिया आपने, चलिए, धन्यवाद । आपको लेकिन बहुत बात कहने को थी ।

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के तौर पर एन.डी.ए. सरकार के द्वारा प्रस्तुत माननीय सुशील मोदी जी द्वारा दिए गए बजट भाषण के समर्थन में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । विपक्ष के लोग बात करते हैं कि आपने किसी भी बजट के आकार का तुलना 2004-05 से क्यों करते हैं । विकास के मानक की तुलना 2004-05 से क्यों करते हैं तो क्या यह सदन को मालूम नहीं होना चाहिए कि 15 साल बनाम 15 साल में विकास के मानक क्या रहे हैं, क्या यह बिहार की जनता को नहीं मालूम होना चाहिए कि इन 15 सालों में क्या कुछ किया गया है । जो उपब्धियां हासिल की गई हैं, वे उपलब्धियां कैसे हासिल की गई हैं क्या उसकी बारीकी के बारे में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? और ये बात तो आंख में पट्टी बांधने के समान होगी कि जब आप अपने इतिहास की तरफ नहीं देखेंगे, इतिहास हमेशा कुछ सिखाता है, इतिहास हमेशा कुछ बताता है, इतिहास हमें हमेशा गलतियों का अहसास कराता है, इसलिए जब भी हम आगे भविष्य की बात करना चाहेंगे तो हमें अपने इतिहास की तरफ मुड़कर जरूर देखना चाहिए और इसलिए आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सुशील कुमार मोदी जी को कि आपके यशस्वी नेतृत्व में आपके वित्त मंत्री के रूप में आपने जो आज 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट बिहार की जनता के लिए प्रस्तुत किया है, उसके लिए पूरे बिहार की जनता आपकी तारीफ कर रही है, पूरे बिहार की जनता इस सरकार की तारीफ कर रही है । आज इस पूरे बजट को देखने के लिए लोग बोलते हैं विजन, कैसा विजन होता है बिहार राज्य के बजट में । आप देखियेगा सर्वाधिक खर्च हम शिक्षा पर करते हैं, सामाजिक मूल्यों पर करते हैं । ग्रामीण विकास पर करते हैं और उन पिछड़े वर्गों के लिए भी करते हैं, चाहे वह महिला हो, चाहे वे बच्चे हो, चाहे वह अनुसूचित जाति-जनजाति हो, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो । आज भी हमारे विपक्ष के नेता सिद्दीकी जी ने कई बातों को कहा कि ग्रीन बजट आयेगा । ग्रीन बजट में हम विभागवाइज, विभागवार और हर विभाग के द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए क्या काम किए जा रहे हैं उसका लेखा-जोखा इस सदन में प्रस्तुत किया जायेगा ।

क्रमशः

टर्न-17/कृष्ण/28.02.2020

श्री मनोज कुमार (क्रमशः) और यह ग्रीन बजट पेश करनेवाला, यह जो विजन है, आपके इस विजन के साथ में, जिससे पूरा विश्व चिंतित हो रहा है, बिहार की सरकार पहली

बार उसके लिये एक मापदंड इस्तेमाल कर रही है, एक विजन दे रही है और यह पूरे देश को, पूरे विश्व को बताने की कोशिश कर रही है कि आप बजट के माध्यम से हर विभाग को, जो विभाग इतने पैसे खर्च करते हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्त्तन के लिये क्या काम किया, उस ग्रीन बजट से बताया जायेगा सदन को ।

आपने कहा कि बिहार में उद्योगों का क्या हाल है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इस देश को एक विजन दिया है, एक मिशन दिया है - वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रोडक्ट । महोदय, बिहार में 38 जिले हैं । आनेवाले समय में इसी बजट के माध्यम से इसी सदन के माध्यम से हम वह विजन लेकर आयेंगे । इन सभी 38 जिलों में कैसा-कैसा हमलोग उद्योग लगा सकते हैं । क्या-क्या हम प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष में उन उत्पादों को लेकर हम जायेंगे और रोजगार का सृजन करेंगे ।

आपने बिहार में शिक्षा की स्थिति के संबंध में कहा, आप कई इन्स्टीच्यूटों का हवाला दे रहे थे, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने भी 1992-93 में मैट्रिक पास किया था । मैं उस समय जब कॉलेजों में गया और बिहार की शिक्षा की स्थिति को देखा, बिहार में कॉलेजों में जो कदाचार देखा, पढ़ाई से मन उबने लगा था, पढ़ाई से नफरत होने लगा था और एक बगावत आने लगा था कि बिहार के विद्यार्थियों में । बिहार में उस 90 के बाद से क्या स्थिति कर दी गयी और जो हमारे यहां बेरोजगारी की बात करते हैं और बेरोजगारी दूर हटाने की बात करते हैं, अगर बिहार में बेरोजगरी बढ़ी है तो उसका शुरूआती दौर 1990 के बाद चालू हुआ है । जब आपने शिक्षकों की बहाली में और विश्वविद्यालयों की बहाली में आपने हायर एजुकेशन को चौपट कर दिया, आपने मिड्ल एजुकेशन को चौपट कर दिया, आपने प्राईमरी एजुकेशन को चौपट कर दिया और उसका नतीजा निकला कि 2003 में शिक्षा मित्र की बहाली किये, शिक्षा मित्र की बहाली इसलिये किये कि बंद पड़े स्कूलों का ताला खोला जा सके । शिक्षा मित्र की बहाली में आपने 1500 रूपये का मानक रखा । क्या आपका यह विकास था ? आपने बिहार की पूरी पीढ़ी को शिक्षा देने से वंचित कर दिया । आज 2006 के बाद में हमने शिक्षा प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया, सरकार शिक्षा को सुधारने के लिये लगातार प्रयास कर रही है । 2006 में नियोजन नीति लायी गयी, उसके बाद 2011 में हमने शिक्षकों के लिये टेट एक्जाम अयोजित करवाया । इस टेट एक्जाम में पास हुये लेकिन उसमें भी बहुत सुधार की जरूरत है ।

महोदय, शिक्षा के अनुदान मांग पर बहस होना है । शिक्षा के विषय में विस्तृत तौर पर बहस की जायेगी और उसमें सरकार की ओर से जवाब दिया जायेगा। आप कहते हैं कि हमारा बजट का आकार बढ़ गया, विपक्ष के लोग बोलते हैं कि बजट का आकार बढ़ गया । आपने अन्य राज्यों से तुलना क्यों नहीं की ? तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उस समय जी0एस0डी0पी0 का ऋण लगभग 60 प्रतिशत होता था और आज हमलोगों ने 25 से 30 प्रतिशत के बीच लाया है । क्या ये आंकड़े आपको नहीं देखना चाहिये । बजट के व्यय के संबंध में बोलते हैं कि आप पूरी राशि खर्च नहीं करते हैं । पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि बिहार में जो वित्तीय प्रबंधन है, बिहार में जो वित्तीय अनुशासन है, वह सबसे अच्छा है । बजट खर्च जीरो टॉलरेंस में कल कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित किया है। मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को कि आपने बजट पूर्व परामर्श लिया, लेखानुदान की जरूरत नहीं पड़ी, वह तमाम विजन इस बजट में रखी गयी है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिये । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर हुये सामान्य विमर्श पर अब सरकार उत्तर होगा ।

सरकार का उत्तर

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर पिछले दो दिनों से जो लगातार चर्चा हो रही थी, उसका जवाब देने के लिये मैं सरकार की ओर से खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, इस बजट पुस्तिका के प्रथम पृष्ट पर महात्मा गांधी जी की दो पंक्तियों को उद्धृत किया गय है, मैं इसको यहां कोट करना चाहूंगा।

" पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिये पर्याप्त साधन प्रदान करता है, लेकिन लालच पूरी करने के लिये नहीं ।" महात्मा गांधी ।

और बजट पुस्तिका के अंतिम पृष्ट पर भी महात्मा गांधी के सात सामाजिक पापकर्म का उल्लेख है -

" सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा । "

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि बजट की पुस्तिका पर गांधी जी के ये जो दोनों उद्धरण हैं, यह केवल सत्तापक्ष के लिये नहीं बल्कि विपक्ष के लिये भी यानी पूरे सदन के लिये मार्गदर्शन का काम करेगा ।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता था कि नेता,प्रतिपक्ष की ओर से बजट पर भाषण होगा । तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल मैं फिर बजट पेश करूंगा इस सदन के अंदर तो नेता,प्रतिपक्ष जो हैं, बजट पर भाषण करके अपनी शुरूआत करेंगे ।

(व्यवधान)

भईया, हम आज तक जिन्दगी में कोई चुनाव नहीं हारे हैं । छात्र संघ से लेकर तीन-तीन विधान सभा और एक लोक सभा का चुनाव डेढ़ लाख वोट से जीतकर भागलपुर से जा चुका हूं । इसलिए मुझे परीक्षा देने की जरूरत नहीं है । मैं परीक्षा दे चुका हूं ।

सभापति महोदय, बार-बार इस सदन के अंदर केरल की चर्चा होती है, तमिलनाडु की चर्चा होती है, हम सबों की बहुत स्वाभाविक इच्छा है या इच्छा होती है कि बिहार का महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, केरल के समकक्ष पहुंचा होता, यह हम सबलोगों की इच्छा होना स्वाभाविक है । लेकिन सभापति महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की नहीं है, यह लड़ाई 15 साल बनाम 30 साल की है ।

(व्यवधान)

यानी श्रीबाबू बिहार के अंतिम मुख्यमंत्री थे ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी,1961 को उनकी मृत्यु हो गयी । तो श्रीबाबू जबतक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तभी तक बिहार के अंदर विकास हुआ । श्रीबाबू की मृत्यु के बाद फिर जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब फिर बिहार के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ।

(व्यवधान)

अभी तो शुरू हुआ है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर श्रीबाबू की मृत्यु के बाद केवल कर्पूरी जी को बहुत थोड़ा समय मिला तो जो थोड़ा बहुत विकास हुआ, वह कर्पूरी जी के समय में हुआ । नहीं तो 1961 से लेकर 2005 तक बिहार विकास के मामले में शून्य पर पहुंच गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1961 से लेकर 1990 तक यानी 30 साल, बिहार में 23 मुख्यमंत्री हुये 29 साल के अंदर, दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे 17 दिनों के लिये, विनोदा बाबू बने मुख्यमंत्री 8 महीने के लिये, के0बी0 सहाय बने 3 साल 5 महीने के लिये, यानी कोई मुख्यमंत्री कोई 3 दिन, कोई दो महीने, कोई 4 महीने, कोाई 6 महीने यानी 1961 से लेकर 1990 तक 29 सालों में बिहार में 23 मुख्यमंत्री बने । यानी मुख्यमंत्री का जो औसत कार्यकाल था, वह एक साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं था अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, 2005 के पहले अगर बिहार में विकास हुआ होता तो आज हम केरल को भी मात कर गये होते । हम तमिलनाडू से आगे बढ़ गये होते । लेकिन दुर्भाग्य था अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले और बिहार के अंदर कर्पूरी जी को छोड़कर जितने मुख्यमंत्री हुये, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किये । महोदय, श्रीबाबू के बाद इनसभी लोगों ने अगर विकास किया होता तो बिहार आज विकास की ऊचाईयों पर पहुंच गया होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय,जैसाकि मैने बताया कि 2004-05 में बिहार का बजट, मैं 1990-91 की बात नहीं कर रहा हूं, जब हमने शुरूआत की, उस समय बिहार का बजट क्या था, 2004-05 में बिहार का बजट 243 हजार 885 करोड़ था, जो 2019-20 में 8 गुना से अधिक बढ़कर 2 लाख 501 करोड़ रूपया पहुंच गया ।

क्रमश :

टर्न-18/राजेश-राहुल/28.2.20

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री, क्रमशः और 2020-21 में यह बढ़कर दो लाख 11 हजार 761 करोड़ पहुंच गया अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 से 2005-06 तक 15 साल कुल खर्च कितना हुआ 2 लाख 15 हजार करोड़ और हम लोग के 15 साल में कितना खर्च हुआ, 12 लाख 24 हजार करोड़ अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय जब हम लोगों ने सरकार संभाली 2005-06 में, उस समय प्लान एक्सपेंडिचर योजना व्यय कुल बजट का केवल 21 परसेंट था और गैर योजना व्यय ये 78 परसेंट था अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय 2020-21 में यह

योजना व्यय बढ़कर 49.95 परसेंट हो गया और गैर योजना व्यय केवल 50 परसेंट रह गया । अध्यक्ष महोदय, आप तुलना की बात करते हैं । अध्यक्ष महोदय मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जहां तक विकास दर की बात है, 1990-91 से 2004-05 के बीच 15 साल में बिहार की औसत विकास दर थी वर्तमान मूल्यों पर केवल 9 प्रतिशत और नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की औसत विकास दर है 18.9 प्रतिशत । आपके 15 साल का जो विकास दर था, वह 9 परसेंट था और हम लोगों के विकास दर का औसत 18.9 प्रतिशत है अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय स्थिर मूल्यों पर कान्सटेंट प्राइस पर अगर आपका विकास दर साढ़े चार परसेंट था, तो हम लोग के 15 साल का विकास दर 10 परसेंट से ज्यादा था । आप तुलना करेंगे, हमारे 15 साल की आपके 15 साल से अध्यक्ष महोदय, 1990-91 में बिहार की प्रतिव्यक्ति आय 1990-91 में 3037 रुपए थी और 2004-05 में यह बढ़कर हुआ 8000 रुपया और मैं सदन को बताना चाहूंगा आपका अन्तिम काल में 8000 था प्रतिव्यक्ति आय और नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2018-19 में ये चार गुना बढ़कर 43822 करोड़ रुपए हो गया है । अध्यक्ष महोदय, अभी सिद्दिकी साहब कह रहे थे कि आपका कर राजस्व क्या था ? अध्यक्ष महोदय, ओन टैक्स रेवेन्यू क्या था, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1990-91 में 1140 करोड़ रुपया आपने खर्च किया था विकास के कामों पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और 2004-05 में 3340 करोड़ रुपया आपने खर्च किया और 2018-19 में हम लोगों ने 1210 से बढ़ाकर 21058 करोड़ रुपया एक साल के अन्दर पूंजीगत परिव्यय करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे सिद्दिकी साहब की आपका अपना कलेक्शन कितना है, तो सिद्दिकी साहब आपको बता दें कि ओन टैक्स रेवेन्यू जो अपना कलेक्शन है 1990-91 में केवल 1140 करोड़ था, 2004-05 में तीन गुना बढ़ा 3340 करोड़ और नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 10 गुना बढ़कर 30 हजार करोड़, ये बिहार का ओन टैक्स रेवेन्यू है अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय अभी नेता भाषण दे रहे थे कि प्रतिव्यक्ति कर्जा कितना है, तो आपको बता दें कि आपके राज्य में प्रतिव्यक्ति कर्जा कितना था, तो मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय कि 1990-91 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का बिहार पर जो कर्जे का बोझ था, वह सकल घरेलू उत्पाद का 64 प्रतिशत था और नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वह घटकर केवल 32 परसेंट रह गया है, महोदय यह केवल 32 परसेंट रह गया है । अध्यक्ष महोदय जो

राजकोषीय घाटा होता है, जो राजकोषीय घाटा है फिजिकल डेफिसिट है, वो 1990-91 में 6 परसेंट था और 2004-05 में 6.2 प्रतिशत था और जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो राजकोषीय घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.60 प्रतिशत रह गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में बिहार ने लगातार पांच वर्षों तक कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार पांच वर्षों तक मिला है । आप बता दें कि आपके 15 साल में एक बार भी कोई पुरस्कार मिला है, एक बार भी आपको पूरे देश में कोई अवार्ड मिला है, नहीं मिला है लेकिन हमारे नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कृषि के क्षेत्र में लगातार पांच सालों तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है और अध्यक्ष महोदय वर्ष 2005-06 में चावल का उत्पादन 35 लाख मैट्रिक टन था, जो 2018-19 में बढ़कर 61 लाख मैट्रिक टन हो गया । अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में चावल की उत्पादकता 10.75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 19.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया अध्यक्ष महोदय । महोदय, 2005-06 में गेहूं का उत्पादन 27 लाख मिट्रिक टन था, जो 2018-19 में बढ़कर 64 लाख मिट्रिक टन हो गया । अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि में गेहूं कि उत्पादकता 13.79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है । अध्यक्ष महोदय, मक्का एवं अन्य मोटे अनाज का उत्पादन 2005-06 में 14 लाख मिट्रिक टन था, जो 2018-19 में बढ़कर 32 लाख 37 हजार मिट्रिक टन हो गया, है और आज रबी की फसल मक्का के क्षेत्र में संपूर्ण देश में हमारा राज्य अग्रणी स्थान पर खड़ा है । अध्यक्ष महोदय वर्ष 2005-06 में सब्जी का उत्पादन 76 लाख मिट्रिक टन था, जो 2018-19 में बढ़कर 1 लाख 67 हजार मिट्रिक टन हो गया है और आज बिहार सब्जी के उत्पादन में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है । अध्यक्ष महोदय, आज मछली के उत्पादन में 2017-18 में जहॉ 5 लाख 87 हजार मिट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था और आज मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि 2019-20 में मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बनने जा रहा है ।

क्रमशः

टर्न-19/सत्येन्द्र/28-02-20

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री(क्रमशः): अध्यक्ष महोदय, तो 33 हजार टन मछलियां बिहार से नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, रांची, गोड्डा आदि शहरों के अन्दर भेजी जा रही है और अध्यक्ष महोदय, अंडा का

उत्पादन जो 2015 में 100 करोड़ था वह 2019-20 में बढ़कर 265 करोड़ होने का अनुमान है। महोदय, एक जमाना था कि चारा घोटला हो गया और पशुपालन मंत्री को जेल जाना पड़ा था, आज भी वे जेल के अन्दर बंद हैं। अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद बिहार में कोई चारा घोटाला नहीं हुआ, कहीं खजाने से अवैध निकासी नहीं हुई और यह है नीतीश कुमार की सरकार, ये है भाजपा और जद(यू0) की सरकार । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जो चारा घोटाला हुआ इसके अन्दर खजाने से 1100 करोड़ रू0 से ज्यादा निकाल लिया गया । उसके दोषी अभी तो जेल में बंद हैं और जिन्दगी भर जेल में बंद रहेंगे, बाहर निकलने की कोई गुंजाईश और कोई संभावना नहीं है।

(व्यवधान जारी)

(इस बीच विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष महोदय,माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार आपदा पर सबसे पहला अधिकार बिहार के गरीबों का है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में दो बार आयी बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में अल्प वर्षापात के कारण अनुग्रह अनुदान, तत्काल सहायता कृषि इनपुट अनुदान, डीजल अनुदान मद में 62 लाख 45 हजार किसानों को 2942 करोड़ रू0 और संरचना पुनर्स्थापन मद में 432 करोड़ रू0, कुल मिलाकर 3374 करोड़ रू0 आपदा पीड़ितों पर खर्च करने का काम किया गया और ये लोग जो बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, जब बिहार में बाढ़ आयी तो कभी बाढ़ पीड़ितों की सूध लेने के लिए नहीं गये, न इन्होंने किसी जिले का दौरा किया न बाढ़ पीड़ितों की आवाज को उठाया । यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जिन्होंने आपदा पीड़ितों पर 3374 करोड़ रू0 हमने खर्च करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय,ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है । अध्यक्ष महोदय, पी0एम0 का जो पैकेज है, एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का जो पी0एम0 का पैकेज है उसमें से 53 हजार करोड़ केवल सड़कों पर खर्च हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा भागलपुर बाईपास, छपरा रेवागंज पथ, डिहरी अकबरपुर पथ, गलगलिया-बहादुरगंज पथ, यह सब वह पथ है जो पूरा हो चुका है। छपरा गोपालगंज, बिहारशरीफ बरबीघा, मोकामा फतुहा, हरनौत बाढ़, सुपौल भपटियाही, गेराबाड़ी कटिहार पथ का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। सोन नदी पर कोईलवर नदी में नये पुल का उसके तीन लेन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने

की संभावना है। महात्मा गांधी सेतु जीर्णोद्धार के उपरांत अप स्ट्रीम वाले दो लेन मार्च, 2020 के अंत तक आम जन के उपयोग हेतु उपलब्ध हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पटना बक्सर फोर लेन, बख्तियारपुर-मोकामा चार लेन, मंझौली से चरौठ पथ, गंगा नदी में सिमरिया 6 लेन पुल, सिमरिया खगड़िया चार लेन, मुंगेर घाट सेतु पहुंच पथ, महेशखूंट वीरपुर बिहपुर पथ, गया दाउदनगर, नासरीगंज विक्रमगंज पथ शामिल है जिन पर कार्य जारी है । सिमरिया 6 लेन पुल के नींव हेतु 18 में से 15 कुएं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार पटना बक्सर फोर लेन पथ की परियोजना के अन्तर्गत बक्सर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 13 में से 9 कुएं का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, कोशी नदी पर सुलौट में चार लेन पुल का निर्माण कार्य 2020-21 में प्रारम्भ करने का लक्ष्य है । गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर फोर लेन सेतु के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त हो चुकी है एवं शीघ्र कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा। पटना गया डोभी के निर्माण हेतु भू-अर्जन कार्य लगभग पूरा किया चुका है एवं उसके निर्माण हेतु तीन खंडों में निविदा प्राप्त कर ली गयी है । निविदा निष्पादन करते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, विक्रमशीला सेतु के समानांतर नये चार लेन पुल के निर्माण हेतु मार्गरेखन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्माण कार्य की स्वीकृति के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। महोदय,पटना रिंग रोड के निर्माण हेतु मार्गरेखन की स्वीकृति हो चुकी है । यह रिंग रोड बिहटा में स्थापित हो रहे नये एयरपोर्ट के पास मिलेगी। यह पथ कन्हौली से प्रारम्भ होकर डुमरी, लखना, बेलदारीचक, कच्चीदरगाह, चकसिकन्दर, सोनपुर दिघवारा, शेरपुर होते कन्हौली में मिलेगी और इसी पथांश में दिघवारा शेरपुर के बीच गंगा नदी पर एक नये छः लेन पुल का निमार्ण भी शामिल है और इसके निर्माण कार्य हेतु डी0पी0आर0 लगभग पूर्ण हो चुका है। महोदय, औरंगाबाद से दरभंगा तक नये चार लेन सड़क पुल का निर्माण प्रस्तावित है । इसका राज्य सरकार द्वारा मार्गरेखन अनुमोदित किया जा चुका है । औरंगाबाद से जहानाबाद होते हुए कच्ची दरगाह विदुपुर पुल पार करते हुए ताजपुर से दरभंगा तक इस पथ का निर्माण किया जायेगा । इसके मार्गरेखन से दक्षिण और उत्तर बिहार के नये इलाके में चार लेन पथों का जाल बिछ सकेगा। इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर रजौली पथ, आरा मोहनियां पथ,

पूर्णिया नारायणपुर पथ के निर्माण हेतु विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भू-अर्जन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु शीघ्र निविदा आमंत्रित की जायेगी । अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैंने आपको सुना दिया कि ये डबल इंजन की सरकार केवल सड़क प्रक्षेत्र में 53 हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाएं बिहार के अन्दर क्रियान्वित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे । भाई, चरवाहा विद्यालय ये हमने थोड़े ही बंद किया, ये तो आप ही ने शुरू किया और आप ही कार्यकाल में चरवाहा विद्यालय बंद हो गया।(क्रमशः)

(व्यवधान जारी)

टर्न-20/मधुप-हेमंत/28.02.2020

....क्रमशः...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अरूण बाबू, चरवाहा विद्यालय हमलोगों ने बंद नहीं किया, यह आप ही की सरकार थी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थीं, बिहार का चरवाहा विद्यालय बंद कर दिया गया । मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में चरवाहा विद्यालय क्यों बंद हुआ ? हमने चरवाहा विद्यालय बंद नहीं किया ।

यहाँ हमारे कांग्रेस के भी मित्र हैं, मैं जानना चाहता हूँ । राज्य में आजादी के पूर्व केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज 1986 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया । फिर 1954 में एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर और 1960 में भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज । मैं अपने कांग्रेस और राजद के लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं स्थापित किया । अगर हिम्मत थी तो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करते । यह तो हमलोगों की सरकार है जिसने बिहार के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज - आप कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बिहार में केवल एक मेडिकल कॉलेज बना, भागलपुर मेडिकल कॉलेज । एक मेडिकल कॉलेज । पी0एम0सी0एच0 बना 1925 में और डी0एम0सी0एच0 बना 1946 में और जो तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे - एन0एम0सी0एच0, एस0के0एम0सी0एच0 और ए0एन0एम0सी0एच0, यह आपने स्थापित नहीं किया था, यह प्राइवेट सेक्टर में स्थापित किया गया था जिसको 1978-79 में कर्पूरी जी की सरकार ने अधिग्रहित करने का काम किया था । आपके 15 साल में और कांग्रेस के 25 साल में बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज

बिहार के अंदर क्यों नहीं स्थापित किया गया ? बिहार के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज इनके समय में स्थापित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद चार नए मेडिकल कॉलेज, एम्स, आई0जी0आई0एम0एस0, बेतिया, पावापुरी सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं । मधेपुरा में 781 करोड़ रू0 की लागत से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 7 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री मधेपुरा में जाकर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सारण, पूर्णिया, समस्तीपुर में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है । वैशाली और झंझारपुर में टेन्डर किया जा चुका है । साथ-ही, बेगुसराय, सीतामढ़ी, बक्सर, जमुई में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है । भोजपुर एवं सीवान में भी नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा । इस प्रकार वर्ष 2005 से अब तक 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा चुके हैं । 112 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं जिसमें 3 निर्माणाधीन हैं, 2 की निविदा प्रक्रिया पूरी है और 4 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । उसी प्रकार निजी क्षेत्र में कटिहार एवं किशनगंज में मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, 2005 के बाद सहरसा, मधुबनी, सासाराम स्थापित किए गए एवं तुर्की, अमहारा (बिहटा) को वर्ष 2020-21 में स्थापना हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज में दलितों का नरसंहार नहीं हुआ था, यह आपका कार्यकाल था कि 1995 से लेकर 2005 के बीच दलितों के सामूहिक नरसंहार का सिलसिला चल पड़ा । 1996 में बथानी टोला में 21 दलित मारे गए थे 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित मारे गए । मियापुर में 32, हैवसपुर में 10, शंकर बिगहा में 23, नारायणपुर में 11 दलित रात के अंधेरे में पंक्ति में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था । यह आपकी सरकार में हुआ। अध्यक्ष महोदय, 5 नवम्बर को एन0डी0ए0 सरकार बनने के बाद नरसंहारों का सिलसिला बंद किया गया और 15 साल में राज्य में एक भी सामूहिक दलित नरसंहार की घटना नहीं घटी ।

अध्यक्ष महोदय, ये दलित की बात करते हैं ? 23 साल तक इन लोगों ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया । चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या राजद की सरकार हो, 23 साल तक राज्य में पंचायत और नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ । 2001 में जब चुनाव कराया गया तो एस0सी0/एस0टी0 को एकल पदों पर आरक्षण का प्रावधान किए बिना चुनाव करा दिया गया । अध्यक्ष महोदय, यह तो 2006 में

एन0डी0ए0 की सरकार आने के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति को 17 परसेंट, अति पिछड़ा को 20 परसेंट और पहली बार महिलाओं को 50 परसेंट का आरक्षण देकर बिहार में पंचायत का चुनाव कराया गया । अध्यक्ष महोदय, 23 वर्षों तक चुनाव नहीं कराने के परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर एस0सी0/एस0टी0 के लोग आरक्षण से वंचित रह गए वहीं वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को मिलने वाले अरबों के अनुदान से भी बिहार वंचित हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने बिहार सरकार के सभी विभागों में सूचना क्रांति को लागू करने का काम किया है और राज्य सरकार की 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध करा दिया गया है । अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हैं, जहाँ पहले 11 रजिस्टर उनको लेकर चलना पड़ता था, जिसका वजन 8.5 किलोग्राम हुआ करता था, अब वह सारी सूचनाएँ स्मार्ट फोन के 10 मोड्युल संधारित किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, अभी तक 1 करोड़ 83 लाख परिवार स्मार्ट फोन पर निबंधित किए जा चुके हैं । इसमें 8 करोड़ 18 लाख की आबादी आच्छादित है और 1 करोड़ 25 लाख लोगों को आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है और इसलिए बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है । अगर बिहार का विकास नहीं हुआ होता तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं होता । 2009 में 4 लाख 23 हजार विदेशी पर्यटक आये थे जिनकी संख्या 2019 में बढ़कर 10 लाख 93 हजार हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, 1216 करोड़ की लागत से भारत सरकार के सहयोग से पटना एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है और बहुत जल्दी 80 लाख यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, दरभंगा, बिहटा तथा पूर्णिया एयरपोर्ट का भी विकास किया जा रहा है और दरभंगा में राज्य सरकार ने एम्स स्थापित करने का निर्णय लिया है और केन्द्र की मदद से हम एम्स का निर्माण दरभंगा में करने जा रहे हैं । इतना ही नहीं, दरभंगा का जो एयरपोर्ट है उसको भी विकसित किया जा रहा है ।

..क्रमशः..

टर्न-21/आजाद/28.02.2020

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : (क्रमशः) दरभंगा का जो एयरपोर्ट है, उसको भी विकसित किया जा रहा है और दरभंगा का जो सैन्य हवाईअड्डा है, वहां सिविल इनक्लेव के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 121 करोड़ रू0 और बिहटा में 108 एकड़ भूमि हेतु 206 करोड़ रू0 और उपलब्ध करा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, अभी सिद्दिकी साहेब वित्त आयोग का जिक्र कर रहे थे । 12वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी घटकर 11.028 परसेंट रह गई थी, जो 13वें में घटकर 10.917 परसेंट और 14वें में 9.665 परसेंट हो गया था । 10 वर्षों के बाद पहली बार बिहार की हिस्सेदारी में .396 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है । अध्यक्ष महोदय, यह हमलोगों के ही प्रयास का परिणाम था कि वित्त आयोग 15 वर्षों के बाद बिहार की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का काम किया है । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों को जो बिहार में आपदा के लिए जहां 2019-20 में 427 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ था, वही 2020-21 में यह बढ़कर 1416 करोड़ रू0 बिहार को प्राप्त होने जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, शहरी निकायों को जहां 2018-19 में 819 करोड़ रू0 का प्रावधान था, वही 2020-21 में 1597 करोड़ रू0 की बढ़ोत्तरी करते हुए 2416 करोड रू0 का प्रावधान किया गया है । पिछले साल बिहार के पटना के अन्दर जल-जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी और एक बड़ी आबादी जल-जमाव से प्रभावित हो गई थी । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने हर संकट को अवसर में बदलने का काम किया है । हर संकट को हमने चुनौती के रूप में लेने का काम किया है । अगर चमकी बुखार से बच्चे मरे तो यह हमारी सरकार है कि जो चमकी बुखार का मुकाबला करने के लिए पूरी योजना बनायी है लेकिन आप कहां थे, जब चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे तो राजद का कोई भी नेता मुजफ्फरपुर झांकने तक नहीं गया था । पटना शहर जल-जमाव में डूबा था तो राजद का कोई भी नेता देखने नहीं गया था । इसलिए पटना शहर को जल-जमाव से मुक्त रखने के लिए हमलोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जितने भी सम्पिंग स्टेशन हैं, उसमें पानी घुसने नहीं दिया जाय, उसके लिए सभी पम्पिंग स्टेशन में पानी घुसने के कारण मोटर पम्प का संचालन बाधित हुआ था । उन पम्प हाऊस में पानी घुसने से रोकने के लिए पम्प हाऊस के दरवाजा पर उच्चतम जल स्तर तक ढ़लान तैयार किया जा रहा है ताकि पानी न घुस सकें । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, 9 करोड़

85 लाख की लागत से सभी ड्रैनेज पम्पिंग स्टेशन के अन्दर सिविल स्ट्रक्चर के मरम्मती का जो कार्य है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, 39 ड्रैनेज पम्पिंग स्टेशन को सात ग्रुप में बांटकर मोटर पम्प, ट्रांसफर्मर, स्वीच पैनल की व्यापक मरम्मती के साथ तीन साल के मेनटेनेन्स के लिए हमने निविदा आमंत्रित कर दिया है और बहुत जल्दी पटना में जो पम्पिंग स्टेशन है, उनको तीन साल के लिए मरम्मती का कार्य दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, सैदपुर, रामपुर, संदलपुर, आर0एम0आर0आई0, बहादुरपुर टी0वी0 टावर, वाटर ड्रैनेज प्रस्तावित नये डी0पी0एस0 के निर्माण के लिए भी कार्य हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, सभी पुराने ड्रैनेज पम्पिंग स्टेशन 31 अदद वी0टी0 पम्प, 19 अदद सेंटीफ्यूगल पम्प, 29 अदद समरसेबुल पम्प, 12 अदद ट्रौली माऊन्टेड पम्प, 38 अदद डिजल जेनरेटर सेट, 54 अदद ट्रांसफर्मर क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। पटना शहर फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं खगौल नगरीय क्षेत्रों के आसपास के इलाकों को जल-जमाव से मुक्त रखने के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था के तहत समेकित ड्रैनेज प्लान तैयार करके परामर्शी का चयन हेतु प्रस्ताव को आमंत्रित किया गया है ।

(इस अववर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन से बहिगर्मन किया गया)

अध्यक्ष महोदय, मैं पटना के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि पटना के अन्दर जो जल-जमाव की स्थिति पैदा हुई थी, उसको चुनौती के रूप में हमारी सरकार ने लिया है और अगले बरसात के पहले पटना के जितने ड्रैनेज पम्पिंग स्टेशन हैं, उसको सुदृढ़ किया जायेगा और उनकी मरम्मती की जा रही है ताकि भविष्य में पटना इस प्रकार से जल-जमाव की स्थिति से परेशान नहीं हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तकलीफ इस बात की है कि लालू यादव जी को जेल जाना पड़ा । हमलोगों ने जेल भेजने का काम नहीं किया है, अगर जेल गये हैं लालू प्रसाद यादव तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री शिवानन्द तिवारी जी का है, जो आज इनके सबसे बड़े सलाहकार बनकर बैठे हुए हैं। कोर्ट आपको सजा देने का काम किया है, हमने तो विपक्ष के नाते अपने कर्त्तव्य का निर्वाह किया है । हमने तो मामले को उजागर किया, हमने सारे मामले को, सारे डॉक्यूमेंट्स को लोगों के सामने रखने का काम किया । यह सजा श्री सुशील मोदी,

श्री नीतीश कुमार ने देने का काम नहीं किया है बल्कि कोर्ट ने आपको सजा देने का काम किया है और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को और दोजाना साहेब को गुस्सा इस बात का है कि दोजाना साहेब का जो अरबों, खरबों रू0 का जो मॉल बन रहा था, मेरे कारण उनका मॉल बनना बंद हो गया । उनको गुस्सा इस बात का है कि 28 साल के उम्र में नेता, प्रतिपक्ष ने 54 से ज्यादा सम्पत्ति इकट्ठा कर लिया, कोई बता दे, जाकर बताईए लोगों को कैसे बेरोजगारी दूर की जा सकती है, कैसे टिकट के बदले रघुनाथ झा से लिखवा लिया, कांति सिंह से लिखवा लिया, कैसे विधान परिषद् के फोर्थ ग्रेड इम्पलायज से और दान में जमीन-जायदाद और मकान लिखवाकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर लिया । अगर हिम्मत है तो बिहार के युवाओं को बताईए कि किस तरह से दोनों भाईयों ने मिलकर अपनी बेरोजगारी को दूर करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जितना सबूत पेश कर दिया है, कोई बच नहीं पायेगा कानून के दायरे से, जितने दिन आप बच सकते हैं, बच जाईए, फिर आपको कोई बचा नहीं पायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ चुनौती देता हूँ कि कोई नीतीश कुमार पर ऊँगली भी नहीं उठा सकता है । 15 साल हो गया हमलोगों की सरकार का, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया । सृजन घोटाला क्या आरोप है, यह तो राबड़ी देवी थी जिसने सृजन घोटाले का जो कारले था जगदीशपुर में, उसके लिए मकान आवंटित करने का काम तब हुआ, जब बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आज के इस बजट भाषण के माध्यम से इस बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमलोगों ने बिहार के विकास के लिए 15 साल काम किया है, हम आगे भी उसी प्रकार बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे और वह दिन दूर नहीं होगा, जब बिहार को हम देश के विकसित राज्यों के पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि विपक्ष के लोगों ने जिस तरह की नारेबाजी की, वेल में आकर नारा लगाते रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम इससे डिगने वाले नहीं हैं, हम इससे हिलने वाले नहीं हैं । वह जमाना बिजेन्द्र बाबू ने देखा है, लोगों ने देखा है जब नेता, प्रतिपक्ष की कुर्सी पर आकर राजद के गुंडे विधायकों ने हमारे हाथ को मड़ोरने का काम किया था । वह दिन हम लौटकर आने नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, अब लालटेन युग बिहार में लौटकर नहीं आयेगा, बिहार अब एल0ई0डी0 से आगे

की दिशा में बढ़ चुका है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को बजट भाषण सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जब बजट पर हुए विमर्श का जवाब दे रहे थे, उस समय कुछ सदस्य वेल में खड़े होकर नारे लगा रहे थे और जो बातें इधर-उधर से आ रही थी, उसमें जो भी असंसदीय बातें कही गयी हैं, उन सबको प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया जाय ।

माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 25 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।